twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शनिवार, 26 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 250, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

लोकसभा में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति

28 जुलाई को लोकसभा तो 29 को राज्यसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा

नई दिल्ली/एजेंसी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में लगातार पांचवें दिन शुक्रवार को जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी। इस बैठक में गतिरोध समाप्त कर सदन की कार्यवाही सोमवार से सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं ने अध्यक्ष को सदन को सामान्य ढंग से चलाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इसी बीच अगले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तय है। राज्यसभा में इसके लिए 16 घंटे का समय तय किया गया है। मानसून सत्र की सोमवार से हुई शुरूआत के बाद से ही लोकसभा और राज्यसभा में हंगामें के चलते सामान्य कामकाज नहीं हो पाया है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा उठा रहा है। लोकसभा में आज भी व्यवधान जारी रहा। अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यवधान के चलते कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित किया। 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सरकार की ओर से गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को आगे विचार और पारित करने के लिए लाया गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहते

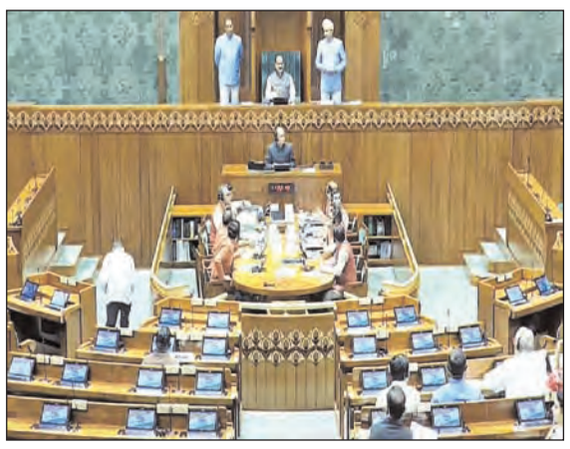

देख पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में आज सुबह चार नए सदस्यों ने शपथ ली। इसके बाद शून्यकाल के आरंभ होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण इसे सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

'सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती'

रिजिजू ने कहा, 'आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक बुलाई और यह दोहराया गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। आज यह निर्णय लिया गया है कि सोमवार (28 जुलाई) को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी।' उन्होंने यह भी कहा कि सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती।

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना एक अगस्त से होगी लागू

रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना 1 अगस्त, 2025 से "पीएम विकसीत भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरआई)" के रूप में लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) स्कीम को पहले ही मंजूरी दे दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दी थी।

99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएमवीबीआरवाई का लक्ष्य 2 साल की अवधि में इस योजना के तहत देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

आर्थिक विकास को गति देने की भारत की कार्यनीति का एक अहम हिस्सा

मंत्रालय के मुताबिक नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न सेक्टरों में नए रोजगार सृजन के लिए लाभ प्रदान करना है। यह रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की भारत की कार्यनीति का एक अहम हिस्सा है। इस योजना में दो भाग हैं, भाग ए पहली बार रोजगार पाने वालों पर केंद्रित है तथा भाग बी नियोक्ताओं पर केंद्रित है:-पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन भाग ए:- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करते हुए इस भाग में एक महीने का ईपीएफ वेतन, अधिकतम 15,000 रुपये दो किश्तों में दिया जाएगा। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।

'न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा'

विपक्ष ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया समेत कई मुद्दे उठाए हैं। हमने उन्हें बताया है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। उसके बाद हम तय करेंगे कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी।

'न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा'

उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। हमें किसी भी संदेह में नहीं रहना चाहिए। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही लोकसभा में शुरू होगी।

बॉक्स

नोटिस को उच्च सदन में स्वीकार नहीं किया गया

सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा में इसी तरह के प्रस्ताव के लिए विपक्ष की ओर से प्रायोजित नोटिस को उच्च सदन में स्वीकार नहीं किया गया है, जिससे निचले सदन में इस प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति की घोषणा करने की उम्मीद है।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम क्या कहता है?

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के अनुसार, लोकसभा में कार्यवाही समाप्त होने के बाद कार्यवाही राज्यसभा में स्थानांतरित की जाएगी। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों ने लोकसभा में नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता मोटर वाहन क्षेत्र के लिए फायदेमंद: सियाम

नई दिल्ली/एजेंसी

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का गर्मजोशी से स्वागत किया है। सियाम ने शुक्रवार को कहा कि इस समझौते से प्रमुख वैश्विक साझेदार के साथ सहयोग और अवसर के लिए नए रास्ते खुलेंगे। सियाम के अध्यक्ष शैलेश चंद्रा ने एक बयान में कहा, हम इस समझौते को एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी के हिस्से के रूप में देखते हैं। यह एक प्रमुख वैश्विक साझेदार के साथ सहयोग और अवसर के लिए नए रास्ते खोलता है। उन्होंने कहा कि सियाम, भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि समझौते के लाभ भारतीय मोटर वाहन उद्योग के लिए अधिक वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी प्रगति में तब्दील हों सकें। चंद्रा ने कहा कि ब्रिटेन के साथ संपन्न ये समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक भागीदारी, खासकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि चूंकि दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं साझेदारी के एक नए चरण में प्रवेश कर रही हैं। ऐसे में वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच इस परिवर्तनकारी समझौते का संपन्न होना आधुनिक व्यापार एवं निवेश ढांचे को आकार देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दशार्ता है। इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में चमड़ा, विद्युत मशीनरी और रसायन जैसे कई घरेलू क्षेत्रों तक शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध होगी, जिससे करीब 23 अरब यूएस डॉलर के व्यापार के अवसर खुलेंगे।

मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ेगा राष्ट्रपति शासन

नई दिल्ली/एजेंसी

केन्द्र सरकार मणिपुर में छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने जा रही है। इस संबंध में राज्यसभा में सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति शासन को छह महीने और बढाने को लेकर मंजूरी मिल गयी है। अब इस प्रस्ताव को राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा। इस संबंध में अभी कोई तारीख तय नहीं की गयी है, लेकिन जल्दी ही इसे सदन में रखे जाने की उम्मीद है।

दिल्ली को कूड़े से आजादी- स्वच्छता अभियान की एक अगस्त से होगी शुरूआत: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली/एजेंसी

दिल्ली सरकार दिल्ली को कूड़े से आजादी- स्वच्छता अभियान की शुरूआत एक अगस्त से कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान में जन-भागीदारी को और पुख्ता करने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में शहरी विकास व शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र सहित शहरी विकास विभाग, लोक

निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली मेट्रो रेल निगम सहित अधिकतर विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एक बयान में बताया कि अगस्त महीना देश की आजादी के लिए जाना जाता है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है कि इस महा दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाई जाए।

संविधान से 'समाजवाद' और 'धर्म निरपेक्ष' शब्द नहीं हटाए

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' और 'धर्म निरपेक्ष' शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब में कहा, कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं। इनसे सार्वजनिक चर्चा या माहौल बनता है, लेकिन यह सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दशार्ता। उन्होंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2024 में खारिज

हो चुकी हैं। बता दें कि आपातकाल के 50 साल होने पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे संविधान का नासूर बताया था। दरअसल 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस दौरान देश में आपातकाल था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी।

धनकड़ के कहा था- ये शब्द नासूर बन गए

इससे पहले निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 26 जुलाई को कहा था कि आपातकाल के दौर में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़े गए 'धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी' शब्द नासूर बन गए हैं। प्रस्तावना पवित्र है और इसे बदला नहीं जा सकता, जोड़े गए शब्द सनातन की भावना का अपमान हैं।

धनकड़ ने कहा- आपातकाल के दौरान 1976 में प्रस्तावना में डाले गए शब्द नासूर थे और उथल-पुथल मचा सकते थे। ये बदलाव संविधान के साथ विश्वासघात का संकेत देते हैं। यह देश की हजारों सालों की सभ्यता-संपदा और ज्ञान को छोटा करने के सिवाय कुछ नहीं है। धनखड़ ने प्रस्तावना को एक बीज बताया, जिस पर संविधान विकसित होता है।

सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को आदेश- दो माह में बनाएं कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम

नई दिल्ली/एजेंसी

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की खुदकुशी और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देश भर के सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों के दो महीनों के अंदर कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम बनाने का आदेश दिया है, जिसमें कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण, छात्रों की सुरक्षा और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य होगा। न्यायालय ने कहा कि कोचिंग सेंटरों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खास उपाय करने होंगे। न्यायालयने कहा कि सभी राज्य सरकारें कोचिंग सेंटरों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा आग से सुरक्षा, बिल्डिंग सुरक्षा, और आपातकालीन निकास जैसे मानकों का पालन करना होगा। छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के लिए एक साफ-सुथरा सिस्टम बनाना होगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों और खासकर कोचिंग सेंटरों को एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति बनानी और लागू करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जिन कोचिंग सेंटरों में 100 या उससे ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, उन्हें कम से कम एक प्रमाणित काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या सोशल वर्कर रखना होगा। इस काउंसलर को बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिन कोचिंग सेंटरों में 100 से कम छात्र हैं उन्हें बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ औपचारिक रेफरल सिस्टम बनाना होगा ताकि जरुरत पड़ने पर छात्रों को प्रोफेशनल मदद मिल सके। उच्चतम न्यायालय ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिया कि वो छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन या पब्लिक शेमिंग के आधार पर बैच में बांटने से बचें क्योंकि इससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है।

पीएम आज तमिलनाडु में विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

नई दिल्ली/एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की राजकीय यात्रा से स्वदेश लौटने के बाद 26 जुलाई को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के दो दिवसीय तमिलनाडु दौरे का कार्यक्रम साझा करते हुए यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में दोपहर करीब 12 बजे आदि तिरुवथिरई

महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर एक विशेष स्मृति सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को रात 8 बजे तूतीकोरिन में आयोजित जनसभा में भाग लेंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें 450 करोड़ की लागत से निर्मित तूतीकोरिन हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन शामिल है। इसकी प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। यह टर्मिनल ऊर्जा दक्षता, जल पुनः उपयोग और हरित भवन मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें एनएच-36 के सेठियाथोपझचोलापुरम खंड को 4-लेन बनाना तथा एनएच-138 के तूतीकोरिन बंदरगाह मार्ग को 6-लेन का बनाना है। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी और माल परिवहन लागत में कमी आएगी।

अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध

नई दिल्ली/एजेंसी

केन्द्र सरकार ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 23 जुलाई को अश्लील और पोर्नोग्राफि क सामग्री वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। निर्देश पत्र के अनुसार यह कार्रवाई गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि मामलों के विभाग, उद्योग निकायों फिक्की और सीआईआई, तथा महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से की गयी। ब्लॉक किए गए ओटीटी प्लेटफार्म में बिग शॉट एप, देसीफिलिक्स, बूमेक्स, न्योनएक्स, नवरास लाइट, गुलाब एप, कंगन एप, बुल एप, शो हिट, जलवा एप, वाओ इंटरटेनमेंट, लुक इंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फुगी, फेनो, शो एक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, अल्ट, हॉट वीआईपी, हलचल एप, मूड एक्स, ट्रीफिलिक्स, उल्लू, मोजफिलिक्स शामिल है।

भारत ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल का किया सफल उड़ान परीक्षण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इससे भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा

नई दिल्ली/एजेंसी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय ओपन एरिया रेंज (एनओएआर) में यूएवी-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, जिसे मानवरहित हवाई प्लेटफार्मों के माध्यम से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों को बधाई देते हुए कहा कि

इससे भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। डीआरडीओ ने यूएलएम-ईआर का एक मॉडल 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया था। यूएलपीजीएम-वी3 एक विस्तारित-रेंज संस्करण है, जिसे हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी कहा जाता है। यह डीआरडीओ की यूएवी-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन (यूएलपीजीएम) हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का विस्तारित रेंज वाला संस्करण है, जिसमें दिन और रात दोनों ऑपरेशनों के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड (आईआर) सीकर के साथ निष्क्रिय होमिंग की सुविधा है। कुरनूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज (एनओएआर) परीक्षण रेंज में यूएवी-लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा है। यह फायर-एंड-फॉरगेट मिसाइल प्लेटफार्म 12.5 किलोग्राम का है, जो छोटे दोहरे जोर वाले ठोस प्रणोदन इकाई से संचालित है। यह दिन में 4 किमी. और रात में 2.5 किमी. की अधिकतम सीमा हासिल कर सकती है। कई वारहेड विकल्पों के साथ इस युद्ध सामग्री को विभिन्न स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

अडानी और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) यूएलपीजीएम परियोजना के लिए प्रमुख विनिर्माण साझेदार हैं, जबकि डीआरडीओ युद्ध सामग्री के विकास और परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यूएलपीजीएम को तीन श्रेणियों यूएलपीजीएम वी1 (बेसलाइन), यूएलपीजीएम वी2 और यूएलपीजीएम वी3 में विकसित किया गया है। वी1, वी2 और वी3 के बीच प्राथमिक अंतर मार्गदर्शन प्रणालियों, प्रदर्शन और रेंज में अंतर हैं। इनमें दिन और रात के ऑपरेशनों के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड (आईआर) सीकर के साथ निष्क्रिय होमिंग की सुविधा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों को बधाई सेते हुए कहा कि इससे भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूएलपीजीएम-वी3 प्रणाली के विकास और सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों, डीसीपीपी, एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को बधाई। यह सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को अपनाने और उनका उत्पादन करने के लिए तैयार है।

मंडी के सरकाघाट में दर्दनाक बस हादसा, पांच की मौत, 20 घायल

एजेंसी

मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस सरकाघाट के मसरेन के पास गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस में सवार 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में 16 वर्षीय युवक सहित पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य महिलाएं की हालत भी नाजुक बनी हुई है। डीएसपी ने मौत की पुष्टि की है। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे मसरेन के त्रांगला गांव के पास एक मोड़ पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस मोड़ से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। सरकाघाट के डीएसपी भी मौके के लिए रवाना हो गए

हैं और उन्होंने हादसे की पुष्टि की है। त्रांगला गांव की एक महिला, मधु ने बताया कि उनके घर के पास ही यह हादसा हुआ है। फिलहाल, घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाने का काम चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार मोड़ पर नियंत्रण खोने से यह दुर्घटना हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पोस्ट करते हुए कहा कि मंडी ज़िला के सरकाघाट उपमंडल के मसेरन के निकट तारंगला में एचआरटीसी बस के खाई में गिरने से पांच लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने और उपचार दिलाने के लिए ज़िला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। दुःख की इस घड़ी में, मैं दिवंगत जनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस हादसे को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी कहा कि मंडी में हुआ बस हादसा बहुत ही दुखद है और मैं ईश्वर से सभी के लिए कुशता की प्रार्थना करता हूं.. प्रशासन से अनुरोध है कि घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करें।

राज्यसभा के 6 सदस्य सेवानिवृत, उज्ज्वल निकम ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की

एजेंसी

नई दिल्ली। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में चौथे दिन भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा के छह सदस्यों को विदाई देने के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 02 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही उज्ज्वल निकम ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने मराठी में शपथ ली। उसके बाद आवश्यक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे गये। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी। एम मोहम्मद अब्दुल्ला (डीएमके), एन चंद्रशेखरन (एआईएडीएमके), अंबुमणि रामदास (पीएमके), एम शनमुगम (डीएमके), वाइको (एमडीएमके) और पी विल्सन (डीएमके) का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त

हुआ। पी विल्सन कल दोबारा सदन में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। इस दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। एमडीएमके नेता वाइको ने राज्यसभा में विदाई भाषण में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईलम तमिलों की त्रासदी और नरसंहार के बारे में 13 बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

तेलंगाना में ओबीसी को 42 फीसदी आरक्षण की सिफारिश पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजारः खरगे

नई दिल्ली। तेलंगाना सरकार ने राज्य में हुए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय निकाय चुनावों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है। इस फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल से खुशी जाहिर की।उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने जिस वैज्ञानिक और व्यापक तरीके से सर्वेक्षण कराया है, वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। इस आधार पर राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 42 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की है, जो अब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय, समानता और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए एक नए आंदोलन की शुरुआत बताया। खरगे ने लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय की लड़ाई दशकों से हाशिए पर पड़े एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदायों को एक सशक्त आवाज दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होने के बावजूद ये समुदाय न्यायपालिका, नौकरशाही, कॉर्पोरेट और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व से वंचित है। उन्होंने

उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में संसद में दिए एक उत्तर के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पदों के लिए ओबीसी वर्ग के 80 फीसदी और एसटी वर्ग के 83 फीसदी पद रिक्त हैं। खरगे ने कहा कि देशभर में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को हटाया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए जाति सर्वेक्षण को जन दबाव में लिया गया फैसला बताया।

चुनाव बहिष्कार को लेकर सहयोगी दलों से करेंगे बातः तेजस्वी यादव

पटना । बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में किसी भी सही मतदाता का नाम नहीं काटे जाने के सरकार द्वारा दिए गए भरोसे के बाद भी इसके विरोध को लेकर विपक्ष के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट की चोरी की पूरी तैयारी है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वोटों की चोरी तो हो ही रही है। उन्होंने कहा, ÷हमलोगों के पास पूरा विकल्प है कि जब बेईमानी ही करना है, चोरी ही करनी है, लोकतंत्र को समाप्त करना है, जनता का अधिकार छीनना है तो हमलोगों का चुनाव बहिष्कार का भी विकल्प खुला है। हमलोग जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं व महागठबंधन के घटक दलों से भी इसे लेकर बात करेंगे। उन्होंने चुनाव में हार के डर से भागने की बात पर कहा कि अगर हार से डरते तो क्या इतनी बार चुनाव लड़ते? चुनाव आयोग जब भाजपा का ही पार्ट बन गया, लाखों वोटरों का वोट काट दिया गया और सदन में खुलेआम झूठ बोला गया, तो क्या है? मृत लोगों के नाम काटे जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हमेशा होता है। पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण को मिला दिया गया। गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ और पुनरीक्षण की अभी फरवरी में लिस्ट आई है। यह तो हर साल की प्रक्रिया है।एसआईआर में संदेह को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक अगस्त के बाद चुनाव आयोग असली खेल करने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा कौन सा बूथ मजबूत है और कौन सा कमजोर है, वैसे उन्हें भी पता होगा कि हमारा कौन सा बूथ मजबूत है और कौन सा कमजोर है। बताया गया कि बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि वोटर लिस्ट से कोई योग्य मतदाता छूटने न पाए और कोई अयोग्य मतदाता जुड़ न जाए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, एसआईआर में अब तक 98.01 प्रतिशत मतदाता कवर किए जा चुके हैं। 20 लाख मृतक मिले, जबकि 28 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम पाए गए।

सेवा में ही मेवा है : राष्ट्रपति ने स्काउट्स एवं गाइड्स को किया सम्मानित, 7 साल बाद पुनर्जीवित हुई परंपरा

एजेंसी

नई दिल्ली। 22 जुलाई 2025 का दिन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण बन गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 उत्कृष्ट सदस्यों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्रमाणपत्र प्रदान किए। यह समारोह 2015 के बाद पहली बार आयोजित किया गया, जिसने लगभग 7 साल से रुकी हुई इस सम्मान की परंपरा को पुनर्जीवित किया। ये पुरस्कार वर्ष 2018 से 2021 तक की अवधि के लिए उनके अद्वितीय समर्पण और सेवा के लिए दिए गए। समारोह की शुरुआत से पहले, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और पदाधिकारियों को राष्ट्रपति भवन प्रोटोकॉल के अनुसार गोदावरी हॉल में लाया गया। इसके बाद, एक औपचारिक बैठक महानदी हॉल में हुई, जिसमें राष्ट्रपति को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का स्कार्फ पहनाया गया और आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दिया गया। पूर्वाह्न 11:10 बजे, राष्ट्रपति ने गोदावरी हॉल में प्रवेश किया, जहां उनका स्वागत सलामी के साथ किया गया। इसके बाद भावपूर्ण तरीके से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की प्रार्थना 'दया कर दान भक्ति का' प्रस्तुत की गई, जिसने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, बीएसजी के

अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जैन ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और बताया कि सभी पुरस्कार विजेता स्काउट/गाइड वचन को जीवन में अपनाते हुए दूसरों की सेवा में सबसे आगे रहे हैं। मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के. के. खंडेलवाल ने संगठन के इतिहास और उसके उद्देश्यों की जानकारी देते हुए गर्व के साथ बताया कि बीएसजी अपनी प्रार्थना और वादे में समर्पण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाला एकमात्र संगठन है। उन्होंने महात्मा गांधी के उस कथन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हर घर में स्काउट्स एवं गाइड्स जैसे प्रशिक्षित बच्चों की कामना की थी। अपने प्रेरणादायक संबोधन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाली, राजस्थान में जंबूरी में अपनी भागीदारी को अविस्मरणीय अनुभव बताया। उन्होंने 50फीसदी पुरुषों और 50फीसदी महिलाओं की भागीदारी की सराहना की, और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को अपनी सदस्यता एक करोड़ तक बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कहाः 'खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिएँ।' और 'सेवा में ही मेवा है', यह मूल्य स्काउट्स एवं गाइड्स में प्रतिदिन व्यवहार में लाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे समर्पित युवाओं के साथ भारत शीघ्र ही अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगा। समारोह के बाद, सभी सदस्यों को ब्रह्मपुत्र हॉल में जलपान के लिए आमंत्रित किया गया और राष्ट्रपति भवन के विभिन्न प्रतिष्ठित कक्षों जैसे अशोक हॉल, नर्मदा हॉल और गणतंत्र हॉल का निर्देशित भ्रमण कराया गया।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या कटवाने के लिए अब भी एक माह का समयः चुनाव आयोग

एजेंसी

नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त और 1 सितंबर के बीच राजनीतिक दल योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वा भी सकते हैं और अगर किसी का नाम गलती से जुड़ गया है तो उसे हटावा भी सकते हैं। चुनाव आयोग का यह वक्तव्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच आया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आदेश पृष्ठ 3, पैरा 7(5) के अनुसार, किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक एक महीने का समय मिलेगा ताकि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करा सकें, जिन्हें बीएलओ/बीएलए ने छोड़ दिया हो। इसके साथ बीएलओ/बीएलए के गलत तरीके से शामिल किए गए

किसी भी मतदाता के नाम को कटवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया अल्पसंख्यक और पिछड़ों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने का तरीका है। विपक्ष के इसी विरोध के चलते पिछले दो दिन से संसद के दोनों सदनों में कोई कार्य नहीं हो पाया है।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में बंद पड़ी कंपनी में चल रही ड्रग की फैक्टरी में पुलिस का छापा, 88 करोड़ की ड्रग बरामद

एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड औद्योगिक एस्टेट में बंद पड़ी कंपनी में चल रही ड्रग फैक्टरी में पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने यहां से 88 करोड़ 92 लाख रुपये मूल्य की 'केटामाइन' नामक प्रतिबंधित ड्रग जब्त की है। इस मामले में महाड एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की टीम ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महाड औद्योगिक एस्टेट में प्लॉट नंबर ई 26/3 में रोहन केमिकल्स नामक कंपनी कई महीनों से बंद थी। लेकिन इसी बंद कंपनी में बड़े पैमाने पर ड्रग का निर्माण किया जा रहा था। इसके बारे में रायगढ़ ग्रामीण पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी। इसके आधार पर रायगढ़ ग्रामीण पुलिस और एमआईडीसी ने बीती रात रोहन केमिकल्स नामक कंपनी पर छापा मारा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 'केटामाइन' नामक प्रतिबंधित पदार्थ बड़े पैमाने पर मिला। इसके

बाद पुलिस ने सभी ड्रग जब्त कर लिया और चार लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों की पहचान मच्छिंद्र भोसले, सुशांत संतोष पाटिल, शुभम सुतार और रोहन गवास के रुप में की गई है। महाड एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है और ये पदार्थ कैसे बेचे गए। इन चारों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(सी), 25, 27(ए), 29, 42 और बी.एन.एस. 2023 की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गहन छानबीन जारी है।

उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

एजेंसी

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गुरुवार को सुबह से उद्योगपति अनिल अंबानी की मुंबई स्थित कंपनियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर-निदेशक अनिल डी अंबानी को %धोखाधड़ी% के रूप में वर्गीकृत करने के कुछ ही दिनों बाद की जा रही है। ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान इससे जुड़े कई सबूत मिले हैं, लेकिन ईडी की टीम ने छापेमारी से संबंधित कोई अधिकृत ब्योरा नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार ईडी की यह कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज दो

प्राथमिकी सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। इसी जानकारी के आधार पर आज सुबह ईडी की टीम मुंबई स्थित अनिल अंबानी के कार्यालयों और संस्थानों पर पहुंची थी और अब तक छापेमारी जारी है। व्यापक जांच के तहत अनिल अंबानी समूह से जुड़े वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों की भी तलाशी ली जा रही है।

ईडी का दावा है कि उसने सार्वजनिक धन को दूसरी जगह भेजने की एक सुनियोजित योजना के सबूत उजागर किए हैं। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनके साथ धोखाधड़ी की गई बताया जा रहा है कि यह जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के संदिग्ध अवैध डायवर्जन पर केंद्रित है। ईडी अधिकारियों के अनुसार समूह की कंपनियों को ऋण वितरित किए जाने से कुछ समय पहले ही बैंक के प्रवर्तकों से जुड़ी संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित कर दी गई थी। अधिकारियों ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से संबंधित निष्कर्ष ईडी के साथ साझा किए हैं। ईडी के मुताबिक कॉर्पोरेट ऋण वितरण में अचानक वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गई। इस मामले में यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े रिश्वतखोरी के पहलू की भी जांच की जा रही है।

'हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे' राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी दी

एजेंसी

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की टिप्पणियों को बकवास बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी इससे बच नहीं सकते क्योंकि ÷हम उनके पास आएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह बयान तेजस्वी यादव की चुनाव बहिष्कार वाली टिप्पणी पर किए गए सवाल पर दिया। उन्होंने एसआईआर मुद्दे पर दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, ÷यह बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ बयान दिया है, यह पूरी तरह से बकवास है। सच तो यह है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर कर्नाटक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करने दी, जिसके 90 प्रतिशत नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत सबूत ठोस हैं। अभी एक निर्वाचन क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद गड़बड़ी का पता चला। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में अर्जित की ऐतिहासिक उपलब्धि

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में खान विभाग ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान पूरे देश में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में पहले पायदान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में अधिसूचित किए गए प्रावधानों से अब तक पूरे देश में प्रधान खनिज के 500 ब्लॉक आवंटित हुए हैं, इनमें से राजस्थान में ही देश के 20 प्रतिशत से अधिक यानी 103 ब्लॉक आवंटित हुए है। वहीं, राज्य सरकार के गत 18 माह के अल्प कार्यकाल में ही 64 ब्लॉकों का ऑक्शन हो चुका है। इस उपलब्धि के बाद राज्य सरकार सभी ब्लॉक्स के शीघ्र परिचालन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश में निवेश और राजस्व की वृद्धि अधिक से अधिक हो सके राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की मंशानुसार खान विभाग ने एक्सप्लोरेशन, डेलिनियेशन, ब्लॉक निर्माण और पारदर्शी ऑक्शन की प्रभावी योजना पर कार्य किया है। जिसके अंतर्गत मिनरल ब्लॉक्स के निस्तारण के संबंध में त्वरित निर्णय

लिए जा रहे है। सरकार के गठन के तीन माह के भीतर ही (मार्च 2024 तक) 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से कर दी गई। वहीं, वर्ष 2024-25 में अकेले 34 ब्लॉकों की नीलामी कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया गया। खान विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में जुलाई तक 15 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है और 12 ब्लॉकों की प्रक्रिया जारी है। वहीं, खान विभाग ने रॉयल्टी राजस्व में एक नया रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2024-25 में रॉयल्टी राजस्व 9 हजार 228 करोड़ रहा है, जो गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक है। नीलाम किए गए ब्लॉकों को जल्द परिचालन में लाने की दिशा में राज्य सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है ताकि निवेश, रोजगार और राजस्व में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। खान विभाग ने जुलाई माह में राजस्व, वन एवं पर्यावरण, भारतीय खान ब्यूरो और स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी (सिया) सहित संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर लाकर खनिज ब्लॉकों और प्लॉटों के परिचालन को गति देने की अभिनव पहल की है। साथ ही, विभाग ने आगामी नवंबर-दिसंबर तक 10 नई खानों को परिचालन में लाने की रणनीति भी बना ली है। प्रशासनिक अनुमतियों को तेजी से निस्तारित करने के लिए पोस्ट-ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल का गठन भी किया गया है, जो विभिन्न विभागों व स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान की उपलब्धि का कारण पारदर्शी और प्रभावी ऑक्शन प्रक्रिया है, जिसकी सराहना केन्द्र सरकार ने भी की है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में कोणार्क, ओडिशा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

एजेंसी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा और डोपिंग नियंत्रण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 लेकर आई है। लोकसभा में विधेयक पेश किया गया। विधेयक विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 2022 के इससे जुड़े अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक का उद्देश्य खेलों में डोपिंग रोधी उपायों को बढ़ावा देना और मजबूत करना तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के संचालन के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करना, तथा खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करना है।विधेयक में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी प्रयोगशाला (एनडीटीएल) के संचालन और संरचना में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसका उद्देश्य दोनों संस्थानों को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और विश्वसनीय बनाना है। विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सुनवाई और अपील की प्रक्रिया क्या होगी। नाडा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही डोप परीक्षण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अपील प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

सीसीआरएएस-प्रयत्न - वैज्ञानिक लेखन कार्यशाला के दूसरे संस्करण की घोषणा

नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) की सीसीआरएएस प्रयत्न वैज्ञानिक लेखन कार्यशाला के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरेट विद्वानों को वैज्ञानिक लेखन, पांडुलिपि विकास और शोध प्रकाशन में महत्वपूर्ण कौशल से सुसज्जित करना है। सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. रविनारायण आचार्य ने इस पहल पर अपने विचार साझा करते हुए युवा आयुर्वेद शोधकर्ताओं को सशक्त वैज्ञानिक लेखन क्षमताओं के साथ सशक्त बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया। प्रो. रविनारायण आचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीसीआरएएस-प्रयत्न पहल, उच्च-गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक प्रकाशन के लिए आवश्यक कौशल से युवा विद्वानों को सशक्त बनाकर आयुर्वेद में एक मज़बूत शोध संस्कृति को पोषित करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सुव्यवस्थित मार्गदर्शन के माध्यम से, प्रयत्न स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट के विद्वानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने शोध को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए सक्षम बना रहा है। पहले सत्र के उत्साहजनक परिणाम इस युक्ति के महत्व की पुष्टि करते हैं और हमें विश्वास है कि आगामी कार्यशालाएं विश्व भर में आयुर्वेद अनुसंधान की उपस्थिति और प्रभाव को और बढ़ाएंगी। अगस्त 2024 में शुरू की गई प्रयत्न कार्यशाला श्रृंखला, अकादमिक अनुसंधान और वैश्विक प्रकाशन मानकों के बीच की खाई को पाटकर आयुर्वेद में अनुसंधान इको-सिस्टम को मज़बूत करने का एक अग्रणी प्रयास है ।

वृत्तचित्र फिल्म कण-कण में राम का विमोचन

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इंटैक) ने अपनी वृत्तचित्र फिल्म कण-कण में राम का विमोचन किया। इंटैक बहुउद्देशीय हॉल में एक विशेष स्क्रीनिंग में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। स्क्रीनिंग के बाद अपने संबोधन में शेखावत ने कहा कि यह फिल्म न केवल एक दृश्यात्मक उत्कृष्ट कृति है, बल्कि रामायण में निहित सार्वभौमिक मूल्यों का एक सांस्कृतिक संकलन भी है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि कैसे यह वृत्तचित्र रामायण को न केवल पौराणिक कथाओं के रूप में, बल्कि एक जीवंत परंपरा के रूप में भी प्रस्तुत करता है जो भारतीय पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। मंत्री शेखावत ने भारत के चल रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण में इंटैक की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। जल शक्ति मंत्रालय में अपने पूर्व अनुभव का उल्लेख करते हुए गंगा सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण परियोजना में इंटैक के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की और भारत, विशेष रूप से गंगा बेसिन के सांस्कृतिक पदचिह्नों को समझने और संरक्षित करने की इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस मौके पर इंटैक के अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकु, इंटैक के सदस्य सचिव रवींद्र सिंह तथा इंटैक के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

कांग्रेस ने बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान राज्य के 52 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई और पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संसद भवन परिसर में मीडिया से कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा इसके जरिए चुनावों को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से बचना चाहती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि यह पहली बार है जब सत्तापक्ष ही खुद संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 52 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर मतदाताओं के नाम काटना सीधे तौर पर लोकतंत्र से नागरिकों की भागीदारी को खत्म करने जैसा है।

समाज और श्रम बाजार पर नई टेक्नोलॉजी के प्रभाव का आकलन जरूरी: मोहन भागवत

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में समाज और श्रम बाजार पर नई टेक्नोलॉजी के प्रभाव का आकलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के जीवन पर टेक्नोलॉजी के प्रभाव को लेकर विचार करना चाहिए। मजदूरों का दुःख समाज का दुःख है। टेक्नोलॉजी मनुष्य का स्वभाव रूखा बनाती है और परिश्रम की प्रतिष्ठा पर प्रश्नचिह्न भी लगाती है। इन सब बातों पर विचार जरूरी है। डॉ. भागवत ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में कहा कि बीएमएस को बड़ा बनाना है। देश के वातावरण में परिवर्तन लाने के साथ-साथ दुनिया के वातावरण में भी बदलाव लाना अपना काम है। संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो संगठन यशस्वी होता है, कार्यकर्ताओं का मान बढ़ता है। भारतीय मजदूर संघ सिर्फ अपना झंडा खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि

श्रमिकों के लिए बनाया गया था।इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, दुनियाभर में अलग-अलग संगठनों के काम करने के अपने-अपने तरीके हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ अनोखा है। यह भारतीय श्रमिकों, भारतीय लोगों और भारतीय जीवन शैली के आधार पर श्रम क्षेत्र में काम करता है। इसने एक विशिष्ट कार्यशैली और प्रणाली विकसित की है।बीएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरन्मय पंड्याजी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की यात्रा 23 जुलाई 1955 को भोपाल में शुरू हुई थी। बीएमएस ने अपनी स्थापना का 70वां वर्षगाठ मनाने की शुरुआत भोपाल से की थी, जिसका समापन आज हो रहा है। उन?होंने कहा कि? भारतीय मजदूर संघ ने अपनी भूमिका केवल यहीं तक सीमित नहीं रखी है। इसकी बजाय समाज और विश्व के कल्याण के व्यापक उपाय जैसे पर्यावरण, सामाजिक समरसता एवं स्वदेशी भी उनके प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा, दिल?ली विधानसभा अध?यक्ष विजेंद्र गुप?ता, अंतरराष?ट्रीय श्रम संगठन के भारत निदेशक मिचिको मियामोतो, संघ के सह-सरकार्यवाह अरुण कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' दिल्ली में हुई कर मुक्त

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को कर मुक्त घोषित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते यह जानकारी साझा की। दिल्ली सरकार से पहले मध्य प्रदेश में यह फिल्म कर मुक्त घोषित हो चुकी है। फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' 18 जुलाई को रिलीज हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने राज्य में फिल्म तन्वी द ग्रेट को कर-मुक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म समावेश की प्रभावशाली कहानी के साथ, यह एक युवा लड़की तन्वी की प्रेरणादायक कहानी है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को

साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तन्वी की कहानी भावनात्मक और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करने और राष्ट्र की चेतना को जागृत करने वाली ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को शुभकामनाएं।

एम्स और जर्मनी के विश्वविद्यालय के बीच करार, मरीजों को मिलेगा अत्याधुनिक चिकित्सा का लाभ

एजेंसी

नई दिल्ली।अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)में मरीजों के इलाज में अब जर्मनी की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

इसके लिए हाल ही में एम्स दिल्ली से डायरेक्टर डॉ.एम. श्रीनिवास के अलावा पांच अन्य विभागों के प्रोफेसर जर्मनी पहुंचे थे। जहां जर्मनी की ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया गया। दोनों मिलकर हेल्थकेयर के क्षेत्र में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शोध कार्य, क्लीनिकल इंटीग्रेशन और डिजिटल तकनीक पर काम करेंगे। इससे मरीजों के इलाज में न केवल तकनीक का उपयोग उच्चतम स्तर पर होगा बल्कि नवाचार से जटिल से जटिल बीमारियों के इलाज की प्रक्रिया में भी सुधार होगा।

एम्स की प्रवक्ता प्रोफेसर रीमा दादा ने बताया कि एम?स और ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी मिलकर यह सिद्ध करेंगे कि कैसे एकेडमिया,

क्लिनिकल मेडिसिन और टेक्नोलॉजी मिलकर काम कर सकते हैं और इसे वैश्विक स्तर पर मरीजों के उन?नत इलाज में बदल सकते हैं। 15 से 18 जुलाई को जर्मनी में हुई वर्कशॉप में डायग्नोसिस से थेरेपी तक हेल्थकेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के इस्तेमाल के नए रास्तों को तलाशा गया। इस दौरान एम्स नई दिल्ली से निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास, डॉ. संदीप अग्रवाल (एचओडी, पीडियाट्रिक सर्जरी), डॉ. नीतीश नायक (प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी), डॉ एमडी रे (प्रोफेसर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी), डॉ. अनीता धर (प्रोफेसर, सर्जिकल डिसिप्लिन), डॉ. कृतिका रंगराजन (एसोसिएट प्रोफेसर, रेडियो डायग्नोसिस) शामिल हुए।

दिल्ली जल बोर्ड में 100 से अधिक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने अपनी तकनीकी टीम की गंभीर कमियों को दूर करने के लिए 100 से अधिक अनुभवी अभियंताओं को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक इस पहल के तहत सिविल और इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल (ईएंडएम) शाखाओं के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये अभियंता विभिन्न सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक एजेंसियों से प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मानसून संबंधी चुनौतियां और शहरी जल की मांग अपने चरम पर है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस योजना को अपनी स्वीकृति देते हुए इसे एक निर्णायक पहल बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जल और सीवरेज परियोजनाएं तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण बाधित रही हैं। 100

से अधिक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति करके हम दिल्ली जल बोर्ड की रीढ़ को मजबूत कर रहे हैं। अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति से परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं अभियंताओं का चयन किया जाएगा जिनका कार्य रिकॉर्ड उत्कृष्ट हो और जिनके पास प्रासंगिक विशेषज्ञता हो। यह प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है ताकि अभियंता शीघ्र सेवा में योगदान दे सकें।उन्होंने कहा कि इस निर्णय के माध्यम से दिल्ली सरकार संस्थागत बाधाओं को दूर करने और एक सक्षम, उत्तरदायी तथा तकनीकी रूप से सशक्त जल बोर्ड का निर्माण करने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। 100 से अधिक अभियंताओं की यह भर्ती दिल्ली की दीर्घकालिक जल अवसंरचना परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

देश में साढ़े पांच हजार करोड़ की साइबर ठगी रोकी, लाखों सिम एवं आईएमईआई ब्लॉक

एजेंसी

नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने देश में साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए विशेष रूप से विकसित नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएफसीएफआरएमएस) के माध्यम से अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों के आधार पर लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये की वित्तीय राशि को साइबर ठगी से बचाने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (ढ्ढ4सी) देशभर में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसके तहत 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' शुरू किया गया है, जहां आम नागरिक ऑनलाइन साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग और धन की हेराफेरी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है। साथ ही साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) भी कार्यरत है, जहां बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों और राज्यों की एजेंसियों के प्रतिनिधि मिलकर रीयल-टाइम कार्रवाई करते हैं।कुमार ने बताया कि सरकार ने अब तक 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और दो लाख 63 हजार 348 मोबाइल आईएमईआई ब्लॉक नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों का विषय है, फिर भी केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मदद और प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग कर रही है। अब तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। 24 हजार 600 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारी, अभियोजक और न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा अब तक 12 हजार 460 मामलों की जांच में राज्यों को सहायता दी जा चुकी है। साथ ही, सीवाईसीटी साइबट्रेन पोर्टल के माध्यम से एक लाख से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हो चुके हैं, और 82 हजार 704 से अधिक को प्रमाण-पत्र भी मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक विशेष एमआईएस प्लेटफ़ॉर्म और प्रतिबिंब नामक विश्लेषण मॉड्यूल शुरू किया गया है, जिससे अपराधियों की गतिविधियों की भू-स्थानिक निगरानी की जा सकती है।

राजेंद्र चोल प्रथम आदि तिरुवथिरई महोत्सव 23 जुलाई से 27 जुलाई तक

एजेंसी

नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में मनाने जा रहा है। 23 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाले आदि तिरुवथिरई महोत्सव के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यातिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस महोत्सव में कलाक्षेत्र फाउंडेशन एक विशेष भरतनाट्यम समूह गायन प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद पारंपरिक ओथुवरों द्वारा देवराम थिरुमुराई का गायन होगा। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित देवराम भजनों पर एक पुस्तिका का औपचारिक विमोचन भी किया जाएगा। महोत्सव का समापन महान उस्ताद पद्म विभूषण इलैयाराजा और उनकी मंडली द्वारा एक संगीतमय प्रस्तुति के साथ होगा, जो चोल युग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिभा को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जुलाई से शुरू होने वाले इस पांच दिवसीय महोत्सव में हर शाम जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर कांग्रेस की नीति स्पष्ट: गुलाम अहमद मीर

एजेंसी

नई दिल्ली । कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर कांग्रेस की नीति स्पष्ट रही है। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन है। इसके मद्देनजर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के इतिहास में आमतौर पर केंद्रशासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा देने की मांग होती रही है, लेकिन पहली बार एक पूर्ण राज्य को विभाजित कर उसे कमजोर किया गया। जम्मू-कश्मीर, जो ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, उसे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया गया। कांग्रेस का मानना है कि यह निर्णय लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ था। इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। मीर ने कहा कि कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी, जब तक जम्मू-कश्मीर को

फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। पार्टी इस मुद्दे को हर मंच पर उठाती रहेगी और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में हुआ था, जहां राहुल गांधी ने चार हजार किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की थी। खराब मौसम और सीमित सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भारी संख्या में लोगों ने यात्रा में भाग लिया, जो कांग्रेस के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है।

नेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न, अध्यक्ष बोले- विधानसभा की पेपरलेस यात्रा में अहम पड़ाव

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में तीन दिवसीय राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह, सामाजिक कल्याण रविंद्र इंद्राज सिंह और विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने नेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नेवा प्रशिक्षण का संपन्न होना विधानसभा की पेपरलेस और प्रौद्योगिकी-आधारित विधायी ढांचे की ओर बढ़ने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने यह बताया कि मानसून सत्र से पूर्व सभी विधायकों के लिए नेवा प्रशिक्षण केंद्र खुला रहेगा ताकि वे इस प्लेटफार्म की विशेषताओं के बारे में और अधिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने मंत्रियों और विधायकों को नेवा प्लेटफार्म के विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे डिजिटल लिस्ट ऑफ बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक पहुंच, नवीनतम तकनीकी अवसंरचना के उपयोग इत्यादि से अवगत कराया। डिजिटल परिवर्तन के तहत मंत्रियों और विधायकों को नेवा मोबाइल एप्लीकेशन से युक्त स्मार्टफोन दिए गए। इस पहल की सराहना करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली विधानसभा ने मात्र 100 दिनों में पूर्णत- पेपरलेस विधायी प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया है।

भारत-नेपाल गृह सचिव स्तरीय वार्ता में सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन पर बनी सहमति

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए दोनों देशों के गृह सचिव स्तर की वार्ता में सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी। गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नेपाल के गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवादी ने की। मंत्रालय के अनुसार, बैठक के दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की समग्र समीक्षा की। इसमें सीमा स्तंभों की मरम्मत और रखरखाव, सीमा पार आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, सीमा जिला समन्वय समितियों की कार्यप्रणाली, और सीमा अवसंरचना को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी), सीमा सड़कें और रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने पर सहमति बनी। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में

सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया गया। दोनों देशों ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई।

बयान में बैठक में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया गया। साथ ही संशोधित प्रत्यर्पण संधि को जल्द से जल्द संपन्न करने की दिशा में काम करने का निर्णय भी लिया गया। वार्ता के अंत में यह तय किया गया कि अगली गृह सचिव स्तर की बैठक नेपाल में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित की जाएगी।

गोवा शिपयार्ड में निर्मित आईसीजी का स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रचेत' लांच

नई दिल्ली। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) में निर्मित दूसरा स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रचेत' लांच कर दिया गया। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत (जीएसएल यार्ड 1267) पिछले साल 29 अगस्त को लांच किया गया था, जिसकी अब जल्द ही आपूर्ति होने वाली है। आज लांच किया गया पोत (जीएसएल यार्ड 1268) जीएसएल में निर्मित दो प्रदूषण नियंत्रण पोत श्रेणियों में से अंतिम पोत है। दूसरे पोत की लांचिंग भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि की मौजूदगी में उनकी पत्नी प्रिया परमेश के हाथों हुई।

इन प्रदूषण नियंत्रण पोतों का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। अपने संबोधन ?में महानिदेशक शिवमणि ने समुद्री क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्रदूषण प्रतिक्रिया पोतों के महत्व और जीएसएल एवं आईसीजी के बीच तालमेल पर प्रकाश डाला। उन्होंने तटरक्षक बल की प्रमुख जहाज निर्माण आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से पूरा करने के लिए जीएसएल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समुद्र प्रचेत का शुभारंभ हमारे देश की जहाज निर्माण क्षमता का एक अनुकरणीय प्रमाण है। उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने पर जीएसएल के कर्मचारियों को बधाई देते हुए आह्वान किया कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना सही दिशा में होना चाहिए।दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत की लांचिंग के साथ जीएसएल और भारतीय तटरक्षक बल आत्मनिर्भरता के पथ पर निरंतर आगे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहा है। समारोह में जीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बृजेश कुमार उपाध्याय, रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारी और जीएसएल के कर्मचारी उपस्थित थे। आईसीजीके कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि इन पोतों को भारतीय तटरक्षक बल की जरूरतों को पूरा करने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और निर्मित किया है। पोत की लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर है।

संपादक की कलम से

कैंसर जोखिमों को परास्त करने में योग सहायक

कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में सुनकर ही लोग डर जाते हैं। कैंसर, वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर और जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं एवं बीमारियों में से एक है, जिसके कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। विश्व कैंसर दिवस दुनिया के हर कोने में कैंसर की रोकथाम, कैंसर के लक्षणों की पहचान और इलाज के प्रति जागरूकता लाने एक महत्वपूर्ण दिन है, इस दिवस को मनाने की शुरूआत साल 2000 में पेरिस में हुई थी। 4 फरवरी 2000 को पेरिस में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर कार्यक्रम का आयोजन कर इस दिवस को मनाने की शुरूआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ हर साल एक खास थीम पर वर्ल्ड कैंसर डे मनाता है। यह खास थीम लोगों को जागरूक करने और कैंसर के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए बनाई जाती है। साल 2025 में वर्ल्ड कैंसर डे की थीम यूनाइटेड बाय यूनीक रखी गई है। इस थीम को रखने का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि कैंसर न सिर्फ इलाज से बल्कि लोगों के आत्मविश्वास एवं मनोबल से जीतने वाली एक लड़ाई है, जिसे हमें जड़ से खत्म करना है। मैं हूँ और मैं करूँगा जो व्यक्तियों से कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बनाने का आह्वान करता है। मानव शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनका समय-समय पर रिप्लेसमेंट होता है। जैसे-जैसे कोशिकाएं मरती जाती हैं उनकी जगह पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन रिप्लेसमेंट के दौरान जो सेल मल्टिप्लीकेशन होता है उसके अंदर कोई एक विकृत कोशिका भी पैदा हो जाती है और यह असामान्य कोशिका ऐसी होती है जिस पर शरीर के सिस्टम्स का कोई नियंत्रण नहीं होता और यह सेल इस तरह मल्टीप्लाई करता है कि अंततोगत्वा यह ट्यूमर अथवा कैंसर का रूप अख्तियार कर लेता है। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं, सभी उम्र के व्यक्तियों में इसका जोखिम देखा जा रहा है। लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज प्राप्त करके कैंसर से मृत्यु के जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। हर साल लाखों लोग कैंसर से मरते हैं, जो विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है। साल 2022 में दुनिया भर में कैंसर से करीब 9.7 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, साल 2040 तक, कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 15.3 मिलियन होने का अनुमान है। दुनिया में हर छठी मौत कैंसर के कारण होती है। मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयोग और तकनीक विकास के चलते कैंसर अब लाइलाज बीमारी तो नहीं रही है, पर अब भी आम लोगों के लिए इसका इलाज काफी कठिन बना हुआ है। कैंसर से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें इस बीमारी के बारे में सब कुछ पता हो, इसे कैसे रोका जाए और इसको कैसे डायग्नोस किया जाए। दुनियाभर में विभिन्न आय, आयु, लिंग, जातीयता आदि के समूहों की आबादी द्वारा सामना की जाने वाली कैंसर देखभाल सेवाओं तक पहुंच में अंतर को खत्म करना अपेक्षित है। असाध्य बीमारी होने के बावजूद इस बीमारी को परास्त किया जा सकता है, अगर जिजीविषा, मनोबल एवं हौसला हो तो कैंसर को भी पस्त किया जा सकता है और ऐसा होते हुए देखा भी जा रहा है। हम जानते हैं कि हममें से हर एक में बदलाव लाने की क्षमता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, और साथ मिलकर हम कैंसर के वैश्विक प्रभाव को कम करने में प्रगति कर सकते हैं। अक्सर वही लोग खतरे में पड़ते हैं, जो खुद को खतरे में महफूज समझते हैं या खतरे को गंभीरता से नहीं लेते हैं।

हाल के वर्षों में हासिल किए गए महत्वपूर्ण कैंसर अनुसंधान मील के पत्थर को साबित हुए हैं और क्षितिज पर आशाजनक नैदानिक विकास का पता लगाया है। पिछले कुछ सालों में विज्ञान ने कैंसर के प्रकारों, कारणों और उपचारों में काफी विकास किया है एवं इस बीमारी से लड़ने एवं इसे परास्त करने में सफलता पाई है। ऐसे तमाम आम और सेलिब्रेटी हैं, जिन्होंने कैंसर का सही समय पर जांच और इलाज करवाकर जीवन का सुख प्राप्त कर रहे हैं। इस दिशा में और भी जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। कैंसर लाइलाज नहीं है, लेकिन इसका इलाज स्टेज 1 या स्टेज 2 में पता लग जाने और तुरन्त ऑपरेशन करके निकाल देने से संभव है। इन वर्षों में अनेक प्रभावी दवाइयों एवं इलाज प्रक्रियाएं भी सामने आयी है जैसे- टागेर्टेड थेरेपी है, इम्यूनो थेरेपी है। उससे लोगों को काफी आराम मिलता है। उससे अनेक लोगों का खतरा पूरी तरह या कुछ मात्रा में कम हुआ एवं जीवन में कुछ वर्ष बढ़े हैं।

कैंसर ठीक होने के सवाल में एक और बात बताना जरूरी हो जाता है कि कैंसर एक लाइफस्टाइल बीमारी भी है। इसलिये जीवन को संतुलित एवं संयममय बनाकर इस बीमारी को कम किया जा सकता है। आप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या आपकी आदतें हैं, क्या आपकी बुरी आदतें है, उसपर भी निर्भर करता है। लाइफस्टाइल और आहार को पौष्टिक रखने के साथ शराब-धूम्रपान को छोड़कर योग, ध्यान एवं साधना के माध्यम से कैंसर के खतरे से बचाव किया जा सकता है। कैंसर विश्वभर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है।

राजनीति और साहित्य के आदर्श पुरूष बालकवि बैरागी

(सुव्रत दवे)

विख्यात साहित्यकार, कवि, गीतकार, श्री बालकवि बैरागी की सात दशकों की साहित्य एवं राजनीति की अनवरत यात्रा का महत्वपूर्ण मुकाम सन् पचास के बाद का समय रहा, जब प्रधानमंत्री पं.नेहरू की गांधीवादी नीतियों से प्रभावित होकर वे कांग्रेस के सदस्य बने व कविताएं भी लिखने लगे। उनकी मुखरता उनके सम्मान का कारण बनी। जब उन्होंने म.प्र. के मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू के समक्ष कविता सुनाई तो उन्हें काटजू जी ने बालकवि की उपाधि दी। तभी से वे नंदराम दास से बालकवि बैरागी के रूप में चर्चित हो गए। सन् साठ के बाद वे राजनीति में अधिक सक्रिय हुए व अपने क्षेत्र में तथा वरिष्ठ इंका नेताओं में चर्चित हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी से उनकी निकटता बढ़ी व पहली बार वे चुनावी राजनीति में इसी दौर में आए और मंत्री बने। श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वे लोकसभा के सांसद रहे। श्री नरसिंह राव के समय कांग्रेस के संयुक्त सचिव बने व श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा टिकट दिए जाने पर राज्यसभा सांसद बनें। राज्यसभा में भी उनकी मुखरता बनी रही वे प्रदेश व देश के हित के मुद्दे समय-समय पर उठाते रहे । राजनीति और साहित्य के दुर्लभ संयोग तथा व्यक्तित्व के धनी श्री बैरागी ने हिन्दी की सेवा राजनीति के माध्यम से भी करने के कई प्रयास किए। संसद के एक सत्र में उन्होंने 28 प्रश्न पूछे जिनमें से अधिकांश राजभाषा हिन्दी के समर्थन व संदर्भ में थे। लेख, कहानी, कविता, छन्द, उपन्यास कई विधाओं के धनी बैरागी जी उन चुनिन्दा साहित्यकारों में से थे, जो चुटकुले व कविता का फर्क समझते हैं। उनके काव्य का स्तर समय के साथ बढ़ता ही रहा। हास्य व व्यंग्य या कटाक्ष भी वे अपने संस्कारों की सीमा की रक्षा करते हुए करते थे। विदेश भ्रमण पर वे कई बार गए व देश के सभी प्रान्तों का भी दौरा उन्होंने किया। सभी बड़े कस्बे, शहर या महानगरों में उनके काव्य पाठ को आनंद व उत्सुकता से सुना जाता था। मंच की गरिमा का उन्होंने सदैव ध्यान रखा, इसलिए वे देशभर में सम्मान के मात्र बने रहे। श्री बैरागी की विलक्षण प्रतिभा के मायने उनके सरल व सहृदय व्यक्तित्व के कारण अधिक बढ़ जाते थे। हर पत्र का उत्तर देना वे अपना कर्तव्य समझते थे। अपने आचरण से वे नेहरू युगीन राजनेताओं का स्मरण कराते थे। दलितों, पिछड़ो व महिलाओं को उन्होंने सदा प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रीय स्तर के कार्य करवाने के बावजूद उन्हें अभिमान व अहंकार छू भी नहीं पाया। उन्होंने अपना समस्त जीवन देशवासियों के लिए ही समर्पित कर दिया।

विकसित भारत 2047 के लिए कृषि सुधारों में व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक

-प्रियंका सौरभ

1965 की एमएसपी व्यवस्था, जिसने मूल्य स्थिरता की गारंटी दी थी, से लेकर आज बाजार एकीकरण, स्थिरता और कल्याण की जटिल समस्याओं से निपटने तक भारत के कृषि सुधारों में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। एमएसपी में बदलाव और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रमों के बारे में हाल की चर्चाएँ कल्याण और अर्थशास्त्र के बीच संतुलन बनाने के प्रयासों को दर्शाती हैं। फिर भी, विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने के लिए टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाना आवश्यक है। चावल और गेहूँ के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके, खाद्यान्न की कमी को कम करने के लिए एमएसपी प्रणाली लागू की गई थी। उदाहरण के लिए, 1966 में मैक्सिकन गेहूँ की किस्मों का आयात करके, भारत ने हरित क्रांति की शुरूआत की, जो चावल और गेहूँ के लिए गारंटीकृत एमएसपी पर निर्भर थी। राजनीतिक दबावों के कारण अंततः अधिक फसलों को कवर करने के लिए एमएसपी का विस्तार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन हुआ।

एमएसपी और मुफ्त बिजली ने पंजाब और हरियाणा को चावल पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है और भूजल कम हो गया है। विशेष रूप से चावल और गेहूँ के लिए, प्रणाली खुली खरीद में बदल गई, जिसके कारण अक्षमताएँ और अधिशेष सूची बन गई। भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का भंडार बफर आवश्यकताओं से लगभग तीन गुना अधिक है, जिससे बबार्दी और भंडारण की समस्याएँ पैदा होती हैं। बिजली, उर्वरक और सिंचाई सब्सिडी की शुरूआत ने किसानों की लागत कम की, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया और मिट्टी को खराब किया। पंजाब में ट्यूबवेल के लिए मुफ़्त बिजली देने से भूजल स्तर में खतरनाक गिरावट आई है। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और डिजिटल लाभार्थी रिकॉर्ड हाल के सुधारों के दो उदाहरण हैं जो दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण पर जोर देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि बिचौलियों को खत्म करती है और किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता देकर लक्षित लाभ वितरण सुनिश्चित करती है।

मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और भूजल की कमी को कम करने के लिए, किसानों को गेहूँ और चावल जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों से दलहन, तिलहन और बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। ओडिशा बाजरा मिशन बाजरा के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जो पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती के उपयोग को कम करते हुए मिट्टी की गुणवत्ता और आय में सुधार करता है। किसानों को उचित मूल्य मिले और विशेष फसलों के अधिक उत्पादन को हतोत्साहित करने के लिए एमएसपी के स्थान पर मूल्य कमी भुगतान योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में, किसानों को भावांतर भुगतान योजना के माध्यम से बाजार मूल्य घाटे के लिए मुआवजा मिलता है, जो बाजार की गतिशीलता को बदले बिना आय स्थिरता बनाए रखता है।

ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती जैसी पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, उर्वरक और बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। पीएम-कुसुम कार्यक्रम सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों को प्रोत्साहित करता है, जो सरकारी सब्सिडी वाली बिजली और भूजल निष्कर्षण पर निर्भरता को कम करता है।

किसानों को फसल चयन, मृदा स्वास्थ्य और जल उपयोग के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करें ताकि संसाधनों को संधारणीय तरीके से अधिकतम किया जा सके। तमिलनाडु में कीटनाशकों को छिड़कने के लिए ड्रोन का उपयोग करने से प्रभावशीलता और पर्यावरण सुरक्षा की गारंटी के साथ-साथ बबार्दी कम होती है।

कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए समान मूल्य निर्धारण की गारंटी के लिए प्रभावी कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ और मूल्य श्रृंखलाएँ बनाएँ। मजबूत आपूर्ति और भंडारण नेटवर्क स्थापित करके, ऑपरेशन ग्रीन्स आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों को स्थिर करना चाहता है। समान वितरण सुनिश्चित करने और संसाधनों की बबार्दी को कम करने के लिए, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को इनपुट सब्सिडी की जगह लेनी चाहिए। उर्वरक वितरण में डीबीटी डायवर्जन को रोककर यह गारंटी देता है कि सब्सिडी योग्य किसानों को प्रभावी ढंग से वितरित की जाती है। उत्पादकता बढ़ाने वाले तरीकों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए छोटे किसानों और बटाईदारों को खुली, विनियमित भूमि पट्टे पर देने की अनुमति देना है।

आंध्र प्रदेश की भूमि पट्टा नीति किरायेदार किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उन्हें लाभ और संस्थागत ऋण तक पहुँच आसान हो जाती है।

बाजार की पहुँच बढ़ाने और बबार्दी को कम करने के लिए भंडारण सुविधाओं, सिंचाई प्रणालियों और ग्रामीण सड़कों पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा दें।

शुष्क क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई कवरेज और जल उपयोग दक्षता में सुधार किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि वानिकी और सूखा प्रतिरोधी किस्मों के विकास का समर्थन करें। किसानों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, पंजाब की कृषि वानिकी नीति जैव विविधता को बढ़ाती है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है। टिकाऊ खेती के तरीके बनाने और विस्तार सेवाओं के माध्यम से सूचना साझा करने की गारंटी देने के लिए कृषि-आरएंडडी खर्च को बढ़ावा दें। क्योंकि यह खर्च कम करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शून्य-जुताई खेती को प्रोत्साहित किया जाता है।

विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने के लिए, कृषि सुधारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है जो कल्याणकारी उपायों को बाजार-संचालित तंत्रों के साथ जोड़ता है। भारत एक ऐसे कृषि क्षेत्र की गारंटी दे सकता है जो समावेशी, लचीला और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो, किसानों को सशक्त बनाए और देश के भविष्य की रक्षा करे, इसके लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान अपनाए जाएँ, टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाए और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

भवन निर्माण में वास्तु शास्त्र की उपयोगिता

(आचार्य राजेश - विभूति फीचर्स)

हर मनुष्य की एक महत्वाकांक्षा अवश्य होती है कि उसका स्वयं का घर हो। वह उसे पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। जब वह इसे पाने के करीब पहुंचता है, तब अपनी सुविधानुसार भवन का मानचित्र बनाना प्रारंभ करता है। वह मानचित्र यदि वास्तुशास्त्रानुरूप हो तो उत्तम फल, सुख, धनसंपत्ति, स्वास्थ्य प्रदान करता है। यदि उसमें अनजाने में कोई दोष आ जाये तो बहुत अधिक कष्टकारी स्थिति निर्मित होती है। यह स्थिति आसानी से नहीं पहचानी जा सकती, कहीं प्रेत आत्माएं उत्पात करती हैं तो कहीं स्वास्थ्य खराब होता है, लाभ की संभावनाएं भी क्षीण होती हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी में मामला उलझ जाता है। इन सब घटनाओं को वास्तुशास्त्र के अलावा अन्य किसी शास्त्र से ठीक नहीं किया जा सकता।

वास्तुशास्त्रद्धते, तस्य न स्याल्ल शलनिश्चयः।
तरमाल्लोकस्य कृपया शास्त्रयेतदुर्दीयते॥

जिस प्रकार हम अपनी सुविधानुसार कमरे, बाथरूम, आंगन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार भवन निर्माण के समय भवन में उपस्थित देवताओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि इन देवताओं का स्थान प्रभावित होता है तो वह भवन के रहवासियों को परेशान करने लगते हैं। वास्तु की सम्पूर्ण कलाओं का वर्णन संक्षिप्त शब्दों में संभव नहीं है। इसलिए इस लेख में भवन निर्माण के मुख्य बिन्दुओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें अपनाकर वास्तु दोष से मुक्त हो सकते हैं। भवन निर्माण में भूमि के बाद सर्वप्रथम महत्व दिशाओं को दिया गया है। दिशाओं से यह निर्धारित होता है कि वास्तुदेवता का कौन सा अंग किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। भवन निर्माण में 8 दिशाएं महत्वपूर्ण हैं। जो क्रमशः इस प्रकार हैं- 1. उत्तर, 2. उत्तर पूर्व (ईशान), 3. पूर्व, 4. दक्षिण पूर्व (आग्नेय), 5. दक्षिण, 6. दक्षिण पश्चिम (नैऋत्य), 7. पश्चिम, 8. उत्तर पश्चिम (वायव्य)

इन आठों दिशाओं का निम्न देवता प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर-कुबेर, ईशान-रूद्र, पूर्व-इंद्र, आग्नेय-अग्नि, दक्षिण-यम, नेऋत्य-अनंत, पश्चिम-वरुण, वायव्य-वायु। भवन का मानचित्र बनाते समय दिशाओं एवं उनके देवताओं का स्थान निश्चित करते हुए कक्षों की स्थापना करें। भगवान विश्वकर्मा ने जो ज्ञान पृथ्वीवासियों को दिया उनके अनुसार भूखण्ड को सोलह भागों में विभाजित कर विभिन्न कक्षों के स्थान को निश्चित किया जाना चाहिए। यह स्थान है- 1. पूजा स्थल, 2. कोषागार, 2. स्नान गृह, 4. दधिमंथन स्थान, 5. रसोई, 6. घृतादि स्थल, 7. शयन कक्ष, 8. शौचालय, 9. शस्त्रागार, सूतिका गृह, 10. स्वाध्याय कक्ष, 11. भोजन कक्ष, 12. दण्डकक्ष, 13. पशुशाला, 14. रतिगृह, 15. औषधिगृह, 16. भण्डारित गृह आदि।

वर्तमान समय में दधिमंथन, घृताधिस्थल, शस्त्रागार, सूतिका गृह, रतिकक्ष, दण्ड कक्ष, औषधिगृह को अलग-अलग स्थान देना संभव नहीं है, अतः आवश्यक कक्षों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है।

1. भवन का मुख्य द्वार - उत्तर या पूर्व दिशा में रखना व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। इस द्वार पर मांगलिक चिन्ह अंकित होना चाहिए। मांगलिक चिन्हों में ऊँ, कलश, गणेश या अपनी-अपनी धार्मिक मान्यतानुसार रख सकते हैं।

2. पूजा स्थल- ईशान कोण इसके लिए सर्वोत्तम होता है। भगवान का मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहे ताकि सेवक का मुंह पूर्व दिशा की ओर रहे, इससे पूजा अर्चना में अच्छी सफलता प्राप्त होती है।

3. रसोई घर- आग्नेय कोण इसके लिए सुरक्षित स्थान है।

स कोण में बिजली का मीटर बोर्ड, बल्व, स्विच लगाना शुभ होता है। अग्नि से संबंधित कोई भी यंत्र नहीं लगाना चाहिए।

4. शयनकक्ष- दक्षिण दिशा में होना चाहिए। यह दिशा सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम मानी गई है।

सिरहाना दक्षिण एवं पैर उत्तर में होना चाहिए।

कांग्रेस की विश्वसनीयता और अधिक गिर सकती रही है

-ललित गर्ग-

कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से विभाजनकारी रही है। इनका एजेंडा ही रहा है देश में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बंटवारा कर-के अराजकता का माहौल बनाना। इसके लिये वह कभी संविधान को खतरे में बताती है तो कभी जातिगत जनगणना की मांग करती है। एक बार फिर डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्मस्थली महू में रैली के दौरान कांग्रेस ने जिस तरह इस पर जोर दिया कि संविधान पर हमला किया जा रहा है और महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, उससे उसकी विचारशून्यता एवं राजनीति अपरिपक्वता ही प्रकट नहीं हो रही है,, बल्कि देश को बांटने की मानसिकता भी उजागर हो रही है। यदि कांग्रेस के रणनीतिकार एवं नेता यह समझ रहे हैं कि वे संविधान के संदर्भ में भय का भूत खड़ा करने और भाजपा एवं संघ के नेताओं के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से देश की जनता को गुमराह करने, बरगलाने में समर्थ हो जाएंगे तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। उलटे इस क्रम में कांग्रेस की विश्वसनीयता और अधिक गिर सकती रही है और वह हास्यास्पद स्थिति का शिकार होकर अपनी राजनीतिक जमीन को कमजोर ही कर रही है। ऐसा हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ है और अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी ऐसे ही होते हुए दिख रहे हैं।

संविधान के खतरे में होने के कांग्रेस के दुष्प्रचार का लाभ भले ही कुछ सीमा तक लोकसभा चुनाव मिला हो, लेकिन हर बार मतदाता ऐसे नारों एवं दुष्प्रचार में गुमराह नहीं होने वाला है। वैसे भी काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस इस बात को भी तूल दे रही है कि महात्मा गांधी के साथ डॉ. आंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। ये ऐसी बातें हैं, जिनका कोई मूल्य-महत्व नहीं। यह सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यह असत्य एवं झूठ की राजनीति है। कांग्रेस भले ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की बातें कर रही हो, लेकिन सच यह है कि वह सामाजिक विभाजन की खाई को चैड़ा करते हुए देश को जोड़ने नहीं, बल्कि तोड़ने में जुटी हुई है। अब मतदाता समझदार हो चुका है, वह ऐसे झूठे प्रचार में बार-बार नहीं आने वाला है। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करते हुए भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाने पर ले रही है, लेकिन कांग्रेस की इन कुचालों का भाजपा एवं आरएसएस करारा जबाव दे रहे हैं।

गत दिवस ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा- बंधुभाव ही असली धर्म है। यही बात डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान-प्रस्तुति के समय अपने भाषण में भी समझाई है। भागवत ने कहा- समाज आपसी सद्भावना के आधार पर काम करता है। इसलिए मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रकृति भी हमें विविधता देती है। वे विविधता को जीवन का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वर्तमान में ही नहीं, बल्कि अतीत में भी विभाजनकारी नीति को बल देते हुए भारतीय इंसानों को बांटती रही है।

गांधीजी ने आजादी के बाद ही यह बात समझ ली थी। इसीलिए गांधीजी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस गांधी के अनुसार तो खत्म नहीं हुई लेकिन देश में विभाजनकारी नीति के कारण जनता द्वारा नकारी जा रही है, खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है।

कांग्रेस भारत की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को दबा रही है, सनातन परंपरा को दबा रही है। अनेक वर्षों तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए इतनी बेचैन है कि वो हर दिन नफरत, द्वेष एवं घृणा की राजनीति कर रही है। कांग्रेस सांप्रदायिकता और जातिवाद के विष को दिल्ली चुनाव में भी उडेल रही है। हिंदू समाज को तोड़ना और उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना ही कांग्रेस की राजनीति का आधार है और यही उसको रसातल में ले जा रहा है। कांग्रेस की जातिगत जणगणना की मांग भी उसकी विभाजनकारी नीति को ही दशार्ती है। मोदी सरकार जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। सरकार के सामने समस्या केवल यह नहीं है कि जनगणना शीघ्र कराई जाए बल्कि मूल समस्या यह है कि कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की मांग का सामना कैसे किया जाए। विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस जातिगत जनगणना पर जोर दे रही है, जो केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के इरादे से की जा रही है। जातिगत जनगणना का उद्देश्य समाज को चुनावी लाभ के लिए जातियों में गोलबंद करना और जातिगत आरक्षण को तूल देकर वोटबैंक की राजनीति को धार देना है।

इसकी पुष्टि विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी के ऐसे बयानों से होती है कि अमुक-अमुक जाति के लोगों को दबाया जा रहा है। यह और कुछ नहीं, समाज को जानबूझकर बांटने की घातक चेष्टा है। यह सही है कि भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है, लेकिन अब जब यह विभाजन लगातार कम होता जा रहा है, तब जाति जनगणना कराकर जाति की राजनीति करने वालों को सामाजिक विभाजन का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह जातीय वैमनस्य को ही हवा देगा और इससे विभाजनकारी प्रवृत्तियों के सिर उठाने का ही खतरा है। जातिगत जनगणना बेहद जटिल होने के साथ विभाजनकारी भी है। यही कारण है कि 2011 में मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना कराने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक करना सही नहीं समझा था। क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं, जिनकी एक राज्य में सामाजिक और आर्थिक हैसियत दूसरे राज्य से बिल्कुल भिन्न है। इतना ही नहीं, कहीं उनकी गिनती अनुसूचित जाति में होती है तो कहीं पिछड़ी जाति में। जाति जनगणना के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पिछड़ेपन का एकमात्र आधार जाति है। एक समय ऐसा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज शहरों में किसी को इससे मतलब नहीं कि कौन किस जाति का है। जाति जनगणना कराने का मतलब होगा देश को फिर से जातीय विभाजन की ओर ले जाना। इससे बचने में ही समझदारी है।

कांग्रेस एवं विपक्षी दलों का मोदी और भाजपा के विरोध के अलावा कोई साझा उद्देश्य नहीं है, उलटे उनमें दलगत हितों और महत्वाकांक्षाओं का तल्ख टकराव है। दो लोकसभा चुनावों में हाशिये पर रहे विपक्षी दल तीसरे चुनाव के लिए एक साथ तो आए, पर मकसद पूरा न होने पर वापस अपनी-अपनी राह चलने को बेताब हैं।

दो दिनों की यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, स्वागत में उमड़े लोग, एफटीए पर होंगे हस्ताक्षर

एजेंसी

लंदन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को लंदन पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी भरा स्वागत किया। उनके स्वागत में उत्साह से भरे लोगों की भीड़ देखी गई जिनके हाथों में तिरंगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वागत में खड़े लोगों का आभार जताते हुए इसे दिल को छूने वाला बताया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में लंदन पहुंचे हैं, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में इसकी कई तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- यूके में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून दिल को छूने वाला है। दो दिवसीय यात्रा पर लंदन पहुंचे नरेन्द्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में यह ब्रिटेन की चौथी यात्रा है। उनके इस दौरे में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होने हैं जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इस यात्रा के दौरान मोदी, किंग चार्ल्स तृतीय और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर कीर भी खासे उत्साहित हैं।

अमेरिका-जापान के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, ट्रंप ने दी अन्य देशों को चेतावनी

वॉशिंगटन/टोक्यो। अमेरिका और जापान के बीच अब तक की सबसे बड़ी व्यापारिक डील हुई है, जिसमें करीब 550 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा कि जापान पहली बार अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह खोलने पर राजी हुआ है, और इस कदम से अमेरिकी व्यापार को भारी बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं टैरिफ तभी हटाऊंगा जब कोई देश अमेरिका के लिए अपने बाजार खोलने को तैयार हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि अब वह टैरिफ को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अन्य देश अमेरिका के साथ खुलकर व्यापार करें। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, इस डील से लाखों नई नौकरियों का सृजन होगा और इसका 90 फीसदी लाभ अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जापान ने 15 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने पर सहमति जता दी है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित होगा। इसी के साथ ट्रंप ने फिलीपीन्स और इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार समझौतों की घोषणा की है। इन दोनों देशों से आयातित वस्तुओं पर अब 19 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा। यह कदम अमेरिका के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

ईरान का बड़ा संकेतः प्रतिबंध दोबारा लगाए गए तो परमाणु संधि से बाहर हो सकता है देश

संयुक्त राष्ट्र/तेहरान। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर यूरोपीय देशों ने उस पर दोबारा प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, तो वह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से पारंपरिक रूप से बाहर निकलने वाला दूसरा देश बन सकता है। यह बयान ईरानी उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार काजेम गरीबाबादी ने उस वक्त दिया जब शुक्रवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ होने वाली अहम बैठक से पहले राजनयिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गरीबाबादी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, अगर स्नैपबैक प्रावधान के तहत प्रतिबंध फिर से लगाए जाते हैं, तो ईरान और संयम नहीं बरतेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अब तक 1970 की परमाणु अप्रसार संधि का पालन किया है, जबकि देश के भीतर से इस संधि से हटने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर हालिया इजराइली और अमेरिकी हमलों के बाद। गरीबाबादी ने यूरोपीय देशों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, अगर यूरोप की नीतियां अमेरिका के अनुरूप ही होंगी, तो हमारे लिए उनके साथ बातचीत का क्या अर्थ रह जाएगा? फिर हम सीधे अमेरिका से ही क्यों न बात करें? उन्होंने कहा कि राजनयिक प्रयास और संवाद से इस संकट को टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए यूरोप को स्वतंत्र रुख अपनाना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची और गरीबाबादी दोनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी शुक्रवार की बैठक में कोई समाधान निकल सकता है, जिससे प्रतिबंधों और संधि से बाहर निकलने की नौबत टल सके।

ईयू और अमेरिका के मध्य व्यापार विवाद गहराया, समझौते की कोशिशों के बीच जवाबी शुल्क की सूची तैयार

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका के साथ जारी व्यापार विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही एक जवाबी शुल्क की सूची भी तैयार की जा रही है। यह जानकारी यूरोपीय आयोग के व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिल ने बुधवार को एक ईमेल बयान के जरिए दी। गिल ने बताया, ईयू की प्राथमिकता अब भी एक राजनयिक समाधान हासिल करने की है, जिसके लिए तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर गहन बातचीत जारी है। हालांकि, यदि वार्ता विफल रहती है, तो यूरोपीय संघ ने वैकल्पिक विकल्पों की तैयारी भी कर ली है। प्रवक्ता के अनुसार, ईयू ने पहले से मौजूद दो जवाबी सूची (लिस्ट 1 और लिस्ट 2) को मिलाकर एक संयुक्त और सुदृढ़ सूची तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसे अब सदस्य देशों की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस एकीकृत सूची में पहले से 21 अरब यूरो (लगभग 24.6 अरब अमेरिकी डॉलर) के अमेरिकी उत्पादों पर लगे शुल्क शामिल होंगे। साथ ही 72 अरब यूरो मूल्य के अतिरिक्त अमेरिकी निर्यातों को शामिल किया जाएगा।

'वोक एआई' पर ट्रंप ने लगाई पाबंदी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों में वोक (डब्ल्यूओकेई) एआई के उपयोग पर रोक लगाने का एक कड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। अपने आदेश में ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ऐसे एआई से फैक्ट्स प्रभावित होते हैं। ट्रंप ने अपने आदेश में कहा, कई एआई सिस्टम्स विविधिता, समानता, समावेशन (डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी डीईआई) जैसे वैचारिक एजेंडों से प्रभावित हैं, जिससे इतिहास, विज्ञान और तथ्यों की विश्वसनीयता पर आंच आती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब से एजेंसियां केवल उन्हीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएम) को खरीद सकेंगी जो सत्य और वैचारिक तटस्थता के दो सिद्धांतों का गंभीरता से पालन करेंगे।

इस आदेश में कई अहम बातें कही गई हैं, जैसे कि एआई को

वैचारिक रूप से तटस्थ बनाना जरूरी होगा। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, एआई मॉडल्स को सिर्फ सच्चाई और फैक्ट्स के आधार पर जवाब देने चाहिए। उन्हें किसी विचारधारा, जैसे डीईआई, को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें लिखा गया है कि एलएलएम विक्रेताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि मॉडल किसी एक पक्ष से प्रभावित न हो, वरना उनका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी दावा किया कि उनका देश दुनिया का उन्नत एआई ढांचा तैयार करेगा। उन्होंने कहा, ÷ मेरा प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी पर कहीं भी सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव कर सके। वोक शब्द मूल रूप से एक सकारात्मक सामाजिक शब्द था, जिसका मतलब- सामाजिक अन्याय, नस्लवाद, लैंगिक भेदभाव, अलगाववाद जैसे मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, लेकिन हाल के वर्षों में इसका अर्थ और इस्तेमाल बदल चुका है। ये शब्द इन दिनों खुद को पोलिटिकली करेक्ट साबित करने की कोशिश के तहत किया जाता है।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी की पार्टी सदस्यता रद्द

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी की पार्टी सदस्यता रद्द कर दी गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) यानी नेकपा एमाले की केंद्रीय कमिटी की बैठक के निर्णय के बाद उनकी पार्टी सदस्यता रद्द की गई है। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने हाल में नेकपा एमाले की सदस्यता ली थी। इतना ही नहीं उन्होंने पिछले वर्ष और इस वर्ष पार्टी की सदस्यता का नवीकरण भी किया था, लेकिन पार्टी की केंद्रीय कमिटी की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति भंडारी को सक्रिय राजनीति में नहीं आने देने के फैसले के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि तीन दिनों तक चली केंद्रीय कमिटी की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति के सक्रिय राजनीति में आने पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। पोखरेल ने बताया कि पार्टी की वेबसाइट में सक्रिय सदस्यता की सूची से भी उनका नाम हटा दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने काठमांडू में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामने ही सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा की थी।

पूर्व सीजीआई खैरुल हक ढाका में गिरफ्तार

एजेंसी

ढाका। सुबह बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को उनके धनमंडी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा (डीबी) ने ये गिरफ्तारी की है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार %ढाका ट्रिब्यून% के मुताबिक डीबी के संयुक्त आयुक्त मोहम्मद नसीरुल इस्लाम के अनुसार एबीएम खैरुल हक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पूछताछ के लिए उन्हें मिंटो रोड स्थित डीबी मुख्यालय ले जाया गया। फिलहाल गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। खैरुल हक ने 2010 में पदभार ग्रहण करते हुए देश के 19वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष होने पर एबीएम खैरुल हक पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हो गए। हक को साल 2013 में तीन साल के कार्यकाल के लिए लॉ कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें कई बार इस पद पर पुनः नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल के अंत में, बीएनपी समर्थक वकीलों के एक

मंच, बांग्लादेश जातीयतावादी ऐनजीबी फोरम (बीजेएएफ) ने पूर्व एबीएम खैरुल हक की गिरफ्तारी और मुकदमे की मांग की थी। बीएसएस न्यूज एजेंसी के अनुसार, उन पर देश की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। बीजेएएफ के अध्यक्ष एडवोकेट जैनुल आबेदीन ने एक लिखित बयान में दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्यायपालिका के सीधे समर्थन से एक फासीवादी शासन स्थापित किया था। अगर न्यायपालिका ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा किया होता, तो लोकतंत्र को नष्ट नहीं किया जा सकता था। एडवोकेट जैनुल आबेदीन ने खैरुल हक को न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन के पतन का मुख्य जिम्मेदार बताते हुए कहा, इतनी बड़ी तबाही के केंद्र में रहने के बावजूद, न तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और न ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई। इसके बावजूद, उन्हें जवाबदेह ठहराना बांग्लादेश की जनता की एक प्रमुख मांग बनी हुई है।

ट्रंप प्रशासन को एपस्टीन केस में झटका, जज का गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने से इनकार

एजेंसी

वाशिंगटन। द वाल स्ट्रीट जनरल अखबार की विशेष खबर से सुर्खियों में आए जेफरी एपस्टीन केस में ट्रंप प्रशासन को झटका लगा है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध को वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा) के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज रॉबिन रोसेनबर्ग ने ठुकरा दिया। विभाग ने अदालत से इस केस से जुड़ी ग्रैंड जूरी की प्रतिलिपियां (गोपनीय दस्तावेज) सार्वजनिक करने का आग्रह किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को इस केस से संबंधित सभी जरूरी ग्रैंड जूरी दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया था। जज रॉबिन रोसेनबर्ग ने अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध पर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि एपस्टीन की जांच के सिलसिले में 2005 और 2007 के संघीय ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट जारी करने में अदालत

के हाथ बंधे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क में मुकदमे का फैसला आने से पहले जेल में मृत्यु हो गई थी। उनकी महिला मित्र गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया था। वह 20 साल की सजा काट रही है। रोसेनबर्ग ने फैसले में लिखा कि सरकार ने वास्तव में स्वीकार कर लिया है कि अदालत के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि 11वीं अमेरिकी सर्किट अपील अदालत ने एक बाध्यकारी मिसाल कायम की है। सनद रहे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में खुलासा किया गया है कि ट्रंप ने 2003 में एपस्टीन को उनके 50वें जन्मदिन पर एक अश्लील पत्र भेजा था। ट्रंप ने इस खुलासे के बाद द वाल स्ट्रीट जनरल के प्रकाशक, उसके दो पत्रकारों और न्यूज कॉर्प के संस्थापक रूपर्ट मर्डोक पर मुकदमा दायर किया है।

थाईलैंड की कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक, दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

एजेंसी

बैंकॉक। थाईलैंड ने आज सुबह हवाई हमला कर कंबोडिया के दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच छह स्थानों पर झड़प होने की सूचना है। रॉयल थाई आर्मी के उप प्रवक्ता कर्नल रिचा सुक्सुवानन ने कंबोडिया पर हवाई हमले करने की पुष्टि की है। बैंकॉक पोस्ट अखबार की खबर के अनुसार रॉयल थाई आर्मी के उप प्रवक्ता कर्नल सुक्सुवानन ने बताया कि गुरुवार सुबह उबोन रत्चथानी प्रांत से छह एफ-16 लड़ाकू विमान तैनात किए गए। इन लड़ाकू विमानों ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उप प्रवक्ता के अनुसार इससे पहले कंबोडियाई सैनिकों ने पूर्वोत्तर प्रांत सुरिन में एक थाई सैन्य अड्डे पर गोलीबारी और रॉकेट दागे। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया को माकूल जवाब दिया। इस बीच, थाईलैंड का गृह मंत्रालय अपने चार प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों को एहतियात के तौर पर खाली करवा रहा है। थाईलैंड की सेना के अनुसार सुबह 7.35 बजे सूरीन के फानोम डोंग राक जिले में ता मुएन थॉम मंदिर के खंडहरों के सामने एक कंबोडियाई मानवरहित ड्रोन दिखा। इसके बाद छह कंबोडियाई सैनिक हथियारों से लैस होकर थाई सैन्य अड्डे के सामने कंटीले तारों की बाड़ के पास पहुंचे। सैनिकों ने कंबोडियाई समकक्षों से संघर्ष को और न बढ़ाने का आग्रह किया। उनके न मानने पर सुबह 8.20 बजे ता मुएन खंडहरों से लगभग 200 मीटर पूर्व में स्थित मू पा सैन्य बेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई बलों ने आसपास के इलाकों में इस तरह से तोपें तैनात की हैं कि नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद सुबह 8.50 बजे मंदिर के खंडहरों पर तोपें दागी गईं। लगभग 9.15 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने मू पा बेस के पास के इलाके को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक थाई सैनिक घायल हो गया। सुबह 9.40 बजे कंबोडिया ने सी सा केत प्रांत में डॉन तुआन मंदिर के खंडहरों पर बीएम-21 रॉकेट लॉन्चर दागे। सुबह 9.55 बजे कंबोडियाई सेना ने कथित तौर पर सुरिन के कप चोएंग जिले में सीमा क्षेत्र विकास केंद्र के पास एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कम से कम तीन नागरिक घायल हो गए। यह हमले उबोन रत्चथानी प्रांत में चोंग आन मा सीमा पार के पास एक बारूदी सुरंग विस्फोट में पांच थाई सैनिकों के घायल होने के एक दिन बाद किए गए हैं। घायल थाई सैनिकों में से एक का पैर कट गया है। थाई सेना ने कहा कि ये बारूदी सुरंगें हाल ही में कंबोडिया ने बिछाई हैं। उत्तर-पूर्व के लिए जिम्मेदार द्वितीय क्षेत्र सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बूनसिन पैडक्लांग ने सीमा सील करने और सुरिन में मंदिर के खंडहरों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश गुरुवार सुबह से लागू हो गए। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने गुरुवार को फेसबुक पर कहा कि थाई सेना ने ओद्दार मीनचे प्रांत में प्रीह विहियर और ता क्रबेई मंदिरों में कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं।

रूस की अंगारा एयरलाइंस का विमान एन-24 लापता, 46 लोग हैं सवार

एजेंसी

मॉस्को। रूस की प्रमुख एयरलाइंस अंगारा का विमान एन-24 लापता हो गया है। उसमें 46 लोग सवार हैं। उड़ान भरने के कुछ देरबाद इसका संपर्क टूट गया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार आपातकालीन

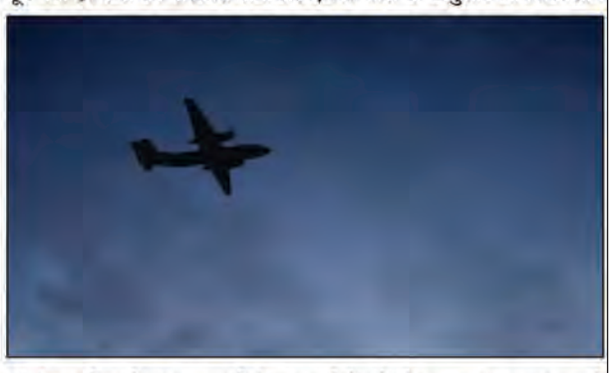

प्रतिक्रिया सेवाओं का कहना है कि 46 लोगों को ले जा रहा एएन-24 यात्री विमान से रूस के अमूर क्षेत्र में संपर्क टूट गया है। एजेंसी तास के अनुसार अंगारा एयरलाइंस का यह विमान टिंडा हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर एक निर्धारित चेकपॉइंट पर संपर्क करने में विफल रहा। इस विमान में दो बच्चों सहित 40 यात्री और छह चालक दल के सदस्य सवार हैं।

यूक्रेन में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय की शक्तियों में कटौती

एजेंसी

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश की संसद वेरखोव्ना राडा से पारित राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एनएबीयू) और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय (एसएपीओ) की शक्तियों में कटौती करने वाले विधेयक पर बीते कल हस्ताक्षर कर दिए। यूक्रेन के लोग वेरखोव्ना राडा के विधेयक पारित करने से खफा हैं। देश में दूसरे दिन भी जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेन के सूचना विभाग की समाचार एजेंसी यूक्रेनफॉर्म ने समाचार को भेजे गए आधिकारिक ई-मेल में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति के दस्तखत होने के साथ ही एनएबीयू और एसएपीओ से जुड़े इस विधेयक ने अब कानूनी शक्ल अख्तियार कर ली। इसका मकसद मार्शल लॉ के दौरान विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के लापता होने पर होने वाली जांच में इन दोनों निकायों की शक्तियों और आजादी पर अंकुश लगाना है। एनएबीयू और एसएपीओ की शक्तियों को कम करने वाले कानून को संसद के आधिकारिक समाचार पत्र होलोस यूक्रेनी में अधिसूचित किया गया है।

यह कानून मार्शल लॉ के दौरान विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के लापता होने से संबंधित घटनाओं की पूर्व परीक्षण जांच की विशिष्टता के संबंध में यूक्रेन की दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के कार्यान्वयन पर जोर देता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अब यूक्रेन का भ्रष्टाचार विरोधी ढांचा रूसी प्रभाव के बिना भी काम करेगा।

उन्होंने कहा कि एनएबीयू के निदेशक सेमेन क्रिवोनोस, एसएपीओ के अभियोजक ओलेक्सांद्र क्लिमेंको, अभियोजक जनरल रुस्लान क्रावचेंको और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वासिल मालियुक से बात की है। हमने विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। सबने माना ऐसा करना जरूरी था। उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं कि एनएबीयू और एसएपीओ को समाप्त कर दिया जाएगा। दोनों काम करते रहेंगे।

गाजा में भुखमरी की चेतावनी को इजराइल ने नकारा, हमास के दुष्प्रचार का हिस्सा बताया

एजेंसी

तेल अवीव। गाजा में इजराइल के रवैये से मानवीय सहायता का संकट और सामूहिक भुखमरी के विभिन्न मानवाधिकार समूहों की चेतावनी को खारिज करते हुए इजराइल ने दावा किया है कि यह हमास के दुष्प्रचार को प्रोत्साहित करने वाला हथकंडा है। इजराइल का दावा है कि गाजा में बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंच रही है जो यूएन द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रही है। इसे इजराइल ने संकट का मुख्य कारण बताया है।

इजराइल के विदेश विभाग की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा में बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता यूएन टीम की तरफ से लिए जाने का इंतजार कर रही हैं।इजराइल का कहना है कि खाद्य सहायता लेकर 4500 ट्रक गाजा में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें बेकरी के लिए

इजराइल के विदेश विभाग की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा में बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता यूएन टीम की तरफ से लिए जाने का इंतजार कर रही हैं।

आटा और 2500 टन शिशु आहार एवं बच्चों के लिए उच्च कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ शामिल है। जबकि गाजा में 700 से ज्यादा मानवीय सहायता वाले ट्रक यूएन की तरफ से उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों और मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति में इसे बाधक बताया है। इजराइल ने उन खबरों को हमास के प्रचारतंत्र का हथकंडा बताया है जिसमें गाजा में व्यापक स्तर पर सामूहिक भुखमरी फैलने की आशंका जताई गई थी। एकदिन पहले सौ से अधिक गैर सरकारी सहायता संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने यह चेतावनी दी थी। इनका कहना था कि इजरायली हमलों और नाकाबंदी की वजह से गाजा में हालात बहुत खराब हैं और वहां व्यापक स्तर पर भुखमरी फैल रही है। इजराइल का कहना है कि युद्धविराम के लिए वार्ता के दौर में इस तरह के दावे हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं और और इस आतंकी संगठन के मंसूबों को मजबूती दे रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन ने हत्या के दोषी अमेरिकी को वेनेजुएला की जेल से रिहा कराया

एजेंसी

वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने हत्या के दोषी एक अमेरिकी व्यक्ति को वेनेजुएला की जेल से रिहा कराया है। अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह कैदियों की अदला-बदली के तहत वेनेजुएला की एक जेल से रिहा किए गए एक व्यक्ति ने तीन लोगों की हत्या की थी। इस व्यक्ति का नाम दाहुद हनीद ओर्टिज बताया गया है। उसके पास अमेरिकी और वेनेजुएला की दोहरी नागरिकता है।द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला की एक जेल से 10 अमेरिकियों और वैधानिक रूप अमेरिका के स्थायी निवासियों की रिहाई सुनिश्चित कराई। विदेशमंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह अहम कदम विदेशों में अन्यायपूर्ण तरीके से बंदी बनाए गए अमेरिकियों की भलाई की रक्षा के प्रयास का प्रतीक है। मैड्रिड स्थित अभियोजक कार्यालय के एक अधिकारी ने पहचान न उजागर करने का आग्रह करते हुए वेनेजुएला के अदालती रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि जेल से रिहा किए गए लोगों में से एक अमेरिकी-वेनेजुएला की नागरिकता प्राप्त दाहुद हनीद ओर्टिज भी है। उसे 2016 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में तीन लोगों की हत्या के लिए वेनेजुएला में दोषी ठहराया गया था। वेनेजुएला की एक अदालत ने 2023 में उसे 30 साल जेल की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तान-ईरान से निकाले गए अफगानों को तालिबान ने दी यातनाएं, मारने की धमकी भी दी

एजेंसी

वाशिंगटन। तालिबान सरकार एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर आ गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान से जबरन निकाले गए कई अफगान नागरिकों को तालिबान ने यातनाएं दीं, धमकाया और मनमाने ढंग से हिरासत में लिया। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान और ईरान लाखों अफगानों को यह कहकर देश से निकाल रहे हैं कि वे अवैध रूप से रह रहे थे।

संयुक्त राष्ट्र मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान लौटे कई लोग तालिबान के हाथों गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार हुए। इनमें वे लोग शामिल हैं जो पहले पश्चिम समर्थित सरकार के लिए काम कर चुके थे या ऐसे पेशे से जुड़े थे जो तालिबान की नजरों में संदेहास्पद हैं। कुछ लोगों को जान से मारने की धमकियां मिलीं, तो कई को गुमनाम रहकर जिंदगी बितानी पड़ रही है।

शारीरिक यातनाओं का दर्दनाक ब्यौरा

रिपोर्ट में एक पूर्व सरकारी अधिकारी का बयान शामिल है, जिसने बताया कि 2023 में लौटने पर उसे बुरी तरह पीटा गया, पानी में डुबोया गया और नकली फांसी

की धमकी दी गई। एक अन्य गैर-बाइनरी व्यक्ति ने कहा कि उसे बंदूक की बट से पीटा गया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि तालिबान के दावों के उलट, लौटने वाले अफगानों के साथ सख्ती बरती जा रही है।

महिलाओं-लड़कियों की स्थिति भयावह

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि किसी को भी ऐसे देश में नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें उनकी पहचान या इतिहास के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़े। उन्होंने अफगान महिलाओं और लड़कियों की स्थिति को विशेष रूप से चिंताजनक बताया, जिन पर तालिबान की सख्त पाबंदियां हैं। जैसे स्कूल बंद, काम करने पर रोक और सार्वजनिक जगहों पर जाने पर प्रतिबंध।

तालिबान की सफाई और यूएन से अपील

तालिबान प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लौटने वालों को दस्तावेज, परिवहन और कानूनी सहायता दी जा रही है। साथ ही, तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वह जबरन निष्कासन को रोके और अफगान शरणार्थियों को खाना, दवा, शिक्षा और आश्रय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए।

अफगान शरणार्थियों का भविष्य संकट में

अफगानिस्तान से लाखों लोग दशकों से अलग-अलग कारणों से बाहर रह रहे थे। अब वे पाकिस्तान, ईरान या अमेरिका जैसे देशों में कानूनी सुरक्षा खो रहे हैं। अमेरिका में हाल ही में एक अदालत के फैसले से हजारों अफगानों की अस्थायी सुरक्षा समाप्त हो गई। ट्रंप प्रशासन की नीतियों और यात्रा प्रतिबंधों ने स्थिति को और खराब बना दिया है।

डिजिटलीकरण से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में आया उछाल

एजेंसी

नई दिल्ली। नये ई-फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत से पिछले चार साल में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या वित्त वर्ष 2020-21 के 6.72 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 9.19 करोड़ पर पहुंच गयी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रीय आयकर दिवस पर लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आयकर देश के आर्थिक तानेबाने की रीढ़ है। यह विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के निर्माण को शक्ति प्रदान करता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि, जीएसटी और अन्य माध्यमों से ट्रैकिंग बढ़ाने के कारण आयकर संग्रह भी उसी तेजी से बढ़ा है। पिछले चार साल में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुने से भी अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 12.31 लाख करोड़ रुपये था जो 2024-25 में 27.02 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मौजूदा सरकार ने पिछले 11 साल में कर आधार बढ़ाकर कर संग्रह बढ़ाने का प्रयास किया है और डिजिटलीकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। भारत में कर प्रणाली का इतिहास काफी पुराना है। कई शासकों ने अपने तरीके से कर लगाये, लेकिन मौजूदा कर प्रणाली की शुरुआत 24 जुलाई 1860 को हुई जब सर जेम्स विल्सन ने आयकर की अवधारणा को लागू किया।

बिजली क्षेत्र में 10 साल में 65 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत : रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश में बिजली की मांग अगले 10 वर्षों में बढ़कर चार ट्रिलियन यूनिट पहुँच जायेगी जिसे पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में 65 से 70 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। ओमनीसाइंस कैपिटल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में साल 2035 तक 1,300 से 1,400 गीगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता स्थापित किये जाने की संभावना है। इसके लिए 65 से 70 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। इसमें पारेषण ग्रिडों और स्मार्ट मीटर लगाने पर करीब 15 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।ओमनीसाइंस कैपिटल के अध्यक्ष और मुख्य पोर्टफोलियो मैनेजर अश्विनी शामी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ते झुकाव को देखते हुए बुनियादी ढाँचे में 65 लाख करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा अवसर है। रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा समय में देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 475 गीगीवाट है जिसमें 220 गीगावाट यानी 46 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा है। साल 2035 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,364 गीगावाट होने की संभावना है जिसमें 971 (71 प्रतिशत) गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा होगी।

वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक भारत मंडपम में

नई दिल्ली । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 25 से 28 सितंबर तक राजधानी के मंडपम में 'वर्ल्ड फ़ूड इंडिया' के चौथे संस्करण की मेज़बानी करने जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को यहां विशेष कार्यक्रम में इस विशाल आयोजन के लिए प्रचार ब्रोशर, वेबसाइट और ऐप का अनावरण किया। श्री पासवान ने ज़ोर दिया कि वर्ल्ड फ़ूड इंडिया महज़ एक व्यापार मेला नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी मंच है जिसका उद्देश्य भारत को खाद्य नवाचार, निवेश और स्थिरता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि कि वर्ल्ड फ़ूड इंडिया का चौथा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 90 से ज़्यादा देशों, 2,000 से ज़्यादा प्रदर्शकों और खेत से लेकर खाने तक की पूरी खाद्य मूल्य श्रृंखला से जुड़े हज़ारों हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान और दूध, बाजरा तथा दालों के प्रसंस्करण में इसके नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हानिकारक प्रभाव के उपचार के लिए संगठित हों छोटी, मझोली फर्म : वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली। देश की छोटी फर्मों को वैश्विक व्यापार में उनके सामूहिक हितों पर किसी अनुचित व्यवहार के कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव के निराकरण के लिए वाणिज्य विभाग की ओर से उन्हें संगठित होने का सुझाव दिया गया है। विभाग के व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक सिद्धार्थ महाजन ने राजधानी में 'व्यापार उपचार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईएस): निष्पक्ष व्यापार हेतु क्षमता निर्माण' विषय पर पिछले दिनों हुई एक तकनीकी कार्यशाला में यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार उपचार कार्यवाहियों में अपने सामूहिक हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटी फर्मों के एकजुट होने और संघ बनाने की बड़ी जरूरत है। कार्यशाला का आयोजन व्यापार और निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) को उपलब्ध व्यापार उपचार व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील बनाकर और इन प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना था।

सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का रुख, सोना और चांदी नए शिखर पर पहुंचे

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी का रुख बना हुआ है। सोना आज 950 रुपये से लेकर 1,040 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 900 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। कीमत में उछाल आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,02,340 रुपये से लेकर 1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 93,810 रुपये से लेकर 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,19,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज

1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,02,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,02,390 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,02,340 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 93,810 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,02,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 93,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना महंगा हुआ है।

रुपये में गिरावट जारी, 3.25 पैसे टूटा

एजेंसी

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर की माँग आने से अमेरिकी मद्रा की तुलना में रुपया 3.25 पैसे टूट गया। कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 86.4125 रुपये का बोला गया। भारतीय मुद्रा लगातार छठे कारोबार दिवस पर कमजोर हुई है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की अनुसंधान विश्लेषक रिया सिंह ने बताया कि रुपया 86.50 रुपये प्रति डॉलर की तरफ बढ़ रहा है जो चार सप्ताह का निचला स्तर है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में हो रही देरी से बाजार में निवेशक आशंकित हैं। विशेषकर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद उनकी चिंता और बढ़ गयी है जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों के खिलाफ ऊंचे आयात शुल्क लगाने की बात कही थी। रुपया आज 8.50 पैसे की गिरावट में 86.4650 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और यही इसका दिन का निचला स्तर रहा। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लिवाली से सुबह के समय यह 86.3450 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ, लेकिन बाजार में डॉलर की माँग निकलने से फिर दबाव में आ गया।दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में रही तेजी से रुपये पर दबाव रहा। हालाँकि कच्चे तेल की कीमतों में 0.7 प्रतिशत की नरमी और भारतीय पूँजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की शुद्ध लिवाली से भारतीय मुद्रा की गिरावट सीमित रही।

एनपीजी ने 97वीं बैठक में रेल और सड़क परियोजनाओं का किया मूल्यांकन

एजेंसी

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बुधवार को नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 97वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव पंकज कुमार ने की।वाणिज?य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि एनपीजी की 97वीं बैठक में रेल और सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इस बैठक में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक प्रभाव के लिए 5 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से तीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की और दो रेल मंत्रालय की थीं। इनमें से दो ब्राउनफील्ड और तीन ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन पीएम-गतिशक्ति के

एकीकृत मल्टीमॉडल अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी और अंतर-विभागीय समन्वय के सिद्धांतों के अनुरूप होने के आधार पर किया गया। इस बैठक में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के मूल सिद्धांतों के अनुरूप मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये पहल रसद दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि, यात्रा समय में कमी और जिन क्षेत्रों में ये सेवाएं प्रदान करती हैं, वहां व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

ईडी ने मिंत्रा और संबंधित कंपनियों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट समर्थित 'फैशन एवं लाइफस्टाइल' प्लेटफॉर्म मिंत्रा, उससे जुड़ी कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उल्लंघन के लिए फेमा के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि बेंगलुर क्षेत्रीय कार्यालय ने मैसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड (मिंत्रा) और उसकी संबंधित कंपनियों एवं उनके निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 16(3) के तहत 1654,35,08,981 (1,654 करोड़ रुपये) के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने कहा कि एजेंसी को 'विश्वसनीय जानकारी' मिली थी कि 'मिंत्रा' ब्रांड नाम वाली मिंत्रा डिजायंस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियां 'थोक कैश एंड कैरी' की आड़ में बहु-ब्रांड खुदरा (एमबीआरटी) कारोबार कर रही हैं। एजेंसी ने कहा कि फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच से पता चला है कि मैसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की थी कि वे थोक कैश एंड कैरी के कारोबार में लगे हुए हैं। इसके जरिए उन्होंने विदेशी निवेशकों से 1654,35,08,981 रुपये के बराबर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है।

लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ 29 जुलाई को खुलेगा, प्राइस बैंड 150-158 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली/मुंबई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निवेशकों के लिए मंगलवार, 29 जुलाई को खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 150-158 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने जारी एक बयान में बताया कि उसका आईपीओ 29 जुलाई को खुलेगा और 31 जुलाई को बंद होगा। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने अपने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले इस आईपीओ के लिए मूल?य का दायरा 150-158 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी की योजना इसके जरिए 254 करोड़ रुपये जुटाने की है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अनुसार निवेशक न्यूनतम 94 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 94 इक्विटी शेयरों के

गुणकों में बोली लगा सकते हैं। ये आईपीओ 18,453,575 इक्विटी शेयरों तक के नए निर्गम और प्रमोटर तथा प्रमोटर समूह के विक्रय शेयरधारकों द्वारा 5,638,620 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का मिश्रण है। कंपनी ने बताया कि नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, ताकि ऋण और सामान्य कंपनी के कामकाज के लिए भविष्य की पूंजीगत जरूरतों को पूरा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो भारत के ऋण बाजार में वंचित ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। ये ग्राहकों को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) ऋण, वाहन ऋण, निर्माण ऋण और अन्य ऋण समाधान सहित विविध उत्पाद पोर्टफोलियो प्रदान करती है। मार्च, 2025 तक इस कंपनी का परिचालन नेटवर्क राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कुल 158 शाखाओं तक फैला हुआ है।

हरित सामग्री, स्वच्छ बिजली से कार्बन उत्सर्जन काफी घटा सकता है घरेलू वाहन उद्योग: सीईईडब्ल्यू

एजेंसी

नई दिल्ली। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य रही राजधानी की प्रतिष्ठित संस्था काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन वाले तरीकों से विनिर्मित हरित इस्पात और स्वच्छ बिजली को अपनाने पर देश में वाहन उद्योग में कार्बन उत्सर्जन का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है।

भारत का वाहन उद्योग कारोबार के हिसाब से विश्व में तीसरे नंबर पर है। सीईईडब्ल्यू की नयी स्वतंत्र अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ बिजली और कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्टील का इस्तेमाल करके 2050 तक अपने उत्पादन उत्सर्जन को 87 प्रतिशत तक कमी ला सकता है। 'हाउ कैन इंडियाज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गो नेट जीरो' एक्सप्लोरिंग डीकार्बोनाइजेशन पाथवेज' (भारत के वाहन विनिर्माण क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के स्तर में शुद्ध वृद्धि शून्य कैसे हो कार्बन उत्सर्जन कम करने की राह की खोज) शीर्षक रिपोर्ट ऐसे समय आयी है जबकि भारत के कई विनिर्माताओं ने बीते दो वर्षों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का अपना उत्पादन बढ़ाया है और इसके साथ ही वे उत्सर्जन कटौती के महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इन ऑटो विनिर्माताओं ने कार्बन उत्सजन स्तर में शुद्ध वृद्धि शून्य करने की वैश्विक परिभाषाओं के अनुरूप लक्ष्य की ओर विज्ञान आधारित पहल (एसबीटीआई) के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए 2050 तक सभी विनिर्माण श्रृंखला में कार्बन उत्सर्जन कम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रमुख वाहन विनिर्माताओं के लिए, आपूर्ति श्रृंखला स्वच्छ बनाने से न केवल उत्सर्जन घटेगा; बल्कि उनकी दीर्घकालिक लागत प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी और वे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो पाएंगे।

एअर इंडिया विमान में टेकऑफ के बाद आई तकनीकी खराबी, कोझिकोड से दोहा जा रहा विमान लौटा

नई दिल्ली। टाटा की अगुवाई वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में लगातार तकनीकी खराबियों के मामले सामने आ रहे हैं। केरल के कालीकट (कोझिकोड) से बुधवार को कतर की राजधानी दोहा जा रहे एयर इंडिया के विमान को उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पायलटों और चालक दल सहित 188 लोगों को लेकर उड़ान संख्या द्वढ्ढ 375 ने सुबह लगभग 9.07 बजे कालीकट से

उड़ान भरी थी। विमान में तकनीकी खराबी आने पर पायलट ने एटीसी (हवाई यातायात नियंत्रण) को जानकारी दी। दो घंटे बाद ही 11.12 बजे वापस केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया। अधिकारी ने कहा कि विमान के केबिन एसी में कुछ तकनीकी समस्या थी, यह आपातकालीन लैंडिंग नहीं थी। इससे एक दिन पहले इससे पहले ही कोच्चि से आ रहा एयर इंडिया का एक विमान मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकल गया था, जिसके बाद विमान को जांच के लिए रोक दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हमारी एक फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के बाद केरल के कालीकट लौट आई। हमने प्राथमिकता के आधार पर एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की। प्रवक्ता ने कहा इस देरी के दौरान मेहमानों को जलपान उपलब्ध कराया और फिर उड़ान रवाना हो गई।

एडीबी ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.50 फीसदी किया

एजेंसी

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने व्यापार अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव को लेकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया है। एडीबी का यह अनुमान अप्रैल में लगाए गए अनुमान 6.70 फीसदी से 0.20 फीसदी कम है।एशियाई विकास बैंक ने बुधवार को जुलाई के जारी एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) में भारत के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के विकास दर अनुमान को भी मामूली रूप से घटाकर 6.80 फीसदी से 6.70 फीसदी कर दिया। एडीबी के जुलाई के एशियाई विकास परिदृश्य के अनुसार यह संशोधन मुख्य रूप से अमेरिकी शुल्क और उससे जुड़ी नीतिगत अनिश्चितता के प्रभाव के कारण किया गया है। ताजा एडीओ के मुताबिक अप्रैल 2025 की तुलना में गिरावट के बावजूद भारत विश?व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। एशियाई विकास बैंक को उम्मीद है कि सेवाएं और कृषि भारत के विकास के प्रमुख चालक होंगे, तथा सामान्य से ज्यादा मानसूनी बारिश के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र को समर्थन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आर्थिक समीक्षा में

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6.30 फीसदी से 6.80 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 6.70 फीसदी के स्तर से घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया है।

चावल महँगा, गेहूँ सस्ता, तेलों में तेजी, चीनी-गुड़ नरम, दालों में घटबढ़

एजेंसी

नई दिल्ली । घरेलू जिंस बाजारों में गेहूँ में नरमी रही जबकि चावल के दाम बढ़ गये। खाद्य तेलों में भी तेजी का रुख रहा। दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया जबकि गुड़ और चीनी के भाव टूट गये। घरेलू थोक बाजारों में चावल की औसत कीमत 17 रुपये बढ़कर 3,820.07 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुँच गयी। गेहूँ पाँच रुपये टूटकर 2,817.06 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटा भी करीब 11 रुपये सस्ता हुआ और 3,274.03 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा।

खाद्य तेलों में तेजी रही। मूँगफली तेल औसतन 38 रुपये प्रति क्विंटल चढ़ गया। सरसों तेल 61 रुपये और सोया तेल करीब 33 रुपये प्रति क्विंटल महँगा हुआ। वनस्पति के दाम में 66 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज की गयी। सूरजमुखी तेल करीब 67 रुपये और पाम ऑयल लगभग 68 रुपये प्रति क्विंटल चढ़ा। दाल-दलहनों में तेजी का रुख रहा। दलहन बाजार में मसूर दाल की कीमत लगभग स्थिर रही। चना दाल 24 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। तुअर दाल का औसत भाव करीब 17 रुपये घट गया। उड़द दाल में करीब 24 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी रही। दाल मूंग में लगभग दो रुपये की मामूली तेजी रही।

गुड़-चीनी : बाजार में गुड़ के औसत भाव करीब चार रुपये प्रति क्विंटल गिर गये। चीनी भी दो रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई है।

मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

एजेंसी

नई दिल्ली। मजबूत ग्लोबल संकेतों और वोलैटिलिटी इंडेक्स में आई गिरावट के कारण घरेलू शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद पहले आधे घंटे के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा, लेकिन सुबह 10 बजे के पहले ही लिवालों ने अपना जोर बना दिया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में तेजी आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.66 प्रतिशत और निफ्टी 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जम कर खरीदारी होती रही। इसी तरह आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर रियल्टी, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज आमतौर पर मजबूती बनी रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब 2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 460.43 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 458.45 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 1.98 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,198 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,997 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,034 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 167 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,649 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,313 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,336 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 23 शेयर बढ़त के साथ और 7 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 38 शेयर हरे निशान में और 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 265.06 अंक की मजबूती के साथ 82,451.87 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के कुछ देर बाद ही बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से पहले आधे घंटे के कारोबार में ही ये सूचकांक फिसल कर 82,279.73 अंक तक आ गया। इसके बाद खरीदारों ने मोर्चा संभाला और आक्रामक अंदाज में लिवाली शुरू कर दी। लगातार हो रही लिवाली के कारण आज का कारोबार खत्म होने के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 599.62 अंक की मजबूती के साथ 82,786.43 अंक तक पहुंच गया। हालांकि आखिरी वक्त में इंट्रा-डे सेटलमेंट की वजह से हुई बिकवाली के कारण सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 60 अंक नीचे फिसल कर 539.83 अंक की बढ़त के साथ 82,726.64 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 78.45 अंक उछल कर 25,139.35 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के कुछ देर बाद ही दबाव बन जाने की वजह ये सूचकांक गिर कर 25,085.50 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद खरीदारों ने चौतरफा लिवाली शुरू कर दी, जिससे इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई।

नाना पाटेकर पर लगाया 'छेड़छाड़' का इल्जाम, राखी पर किया केस, 'आशिक बनाया' गर्ल

तनुश्री दत्ता

के पांच विवाद

बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तनुश्री ने कल देर शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जहां वो फफक-फफक कर रोती नजर आ रहीं थीं. इस वीडियो में तनुश्री काफी ज्यादा परेशान नजर रही थीं. उन्होंने वीडियो में कहा कि काफी लंबे वक्त से उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है. उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करने की भी बात कही थी.ये पहली बार नहीं है, जब तनुश्री ने इस तरह से आवाज उठाई है, या फिर उनका कोई विवाद सामने आया है. इससे पहले भी तनुश्री, कई विवादों का हिस्सा रहीं हैं और कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रही हैं. एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता बॉलीवुड का एक जाना-माना नाम रही हैं. इमरान हाशमी और सोनू सूद संग 'आशिक बनाया आपने' में तनुश्री की एक्टिंग ने सभी का दिल जीत लिया था. ऐसे में आईए जानते हैं तनुश्री से जुड़े कुछ बड़े विवादों के बारे में.

तनुश्री दत्ता और #Metoo मूवमेंट

साल 2018 के तनुश्री दत्ता के #Metoo मूवमेंट में दिए गए बयान ने तो हर किसी को हैरान कर दिया था. तनुश्री ने बॉलीवुड के काफी सीनियर एक्टर नाना पाटेकर पर उनको हैरास करने का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत में उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें सेट पर बदसलूकी करने और गाली गलौज जैसे संगीन आरोप शामिल थे. तनुश्री ने बताया था कि ये सबकुछ उनके साथ फिल्म हॉर्न ओके प्लीजके शूट के दौरान किया गया था. हालांकि, साल 2019 में पुलिस ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी गई थी.

विवेक अग्नीहोत्री पर लगाए थे आरोप

इसके बाद साल 2005 में फिल्म 'चॉकलेट' की शूटिंग के दौरान तनुश्री ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर अपने साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया था. तनुश्री ने कहा कि वो जानबूझकर उन्हें स्कर्ट में पूरी यूनिट के सामने बैठा कर रखते थे. उन्हें अपनी बॉडी ढकने नहीं दी जाती थी. तनुश्री ने विवेक पर उनपर चिल्लाने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और सेट पर शॉट रेडी ना होने के बाद भी उनपर गुस्सा निकालने का आरोप लगाया था. तनुश्री ने बताया कि वो सेट पर कई बार बहुत जल्दी आ जाती थीं, जब लाइट्स भी नहीं लगी होती थीं, फिर भी उनपर चिल्लाया जाता था.

वीडियो में कहा- 'हैरेसमेंट से थक चुकी हूं'

हाल ही में शेयर किए गए वीडियो में तनुश्री ने कहा कि उनके साथ लोग काफी गलत व्यवहार कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन भी शेयर किया, जहां उन्होंने लिखा- मैं बीमार हूं और हैरेसमेंट से थक चुकी हूं. ये 2018 से चल रहा है सद्गद्दह्लश्श.आज परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया. प्लीज कोई मेरी मदद करें. कुछ करें इससे पहले कि देर हो जाए.वीडियो में तनुश्री कहतीं हैं, मुझे अपने घर में ही परेशान किया जा रहा है. मैंने पुलिस को बुलाया. वो आए और उन्होंने मुझे एक प्रॉपर शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है. मैं कल या परसों पुलिस स्टेशन जाऊंगी. मैं ठीक नहीं हूं. मुझे इतना परेशान किया गया पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई. मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूं. मेरा पूरा घर बिखरा बड़ा है.

'बहुत अच्छी हूं जानेमन...' 49 साल की कुंवारी एक्ट्रेस की ये बात सुनकर पिघल गए थे कपिल शर्मा

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो पर अक्सर ही एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं. हालांकि अक्सर ही एक्ट्रेसेस कपिल को कुछ ऐसा जवाब दे जाती हैं कि कपिल की भी बोलती बंद हो जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या बोला जाए. एक बार मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी अपने जवाब से कपिल को हैरान कर दिया था. एक्ट्रेस का जवाब सुनकर कपिल बौखला गए थे.कपिल शर्मा इन दिनों नेटफ्लिक्स पर आ रहे अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन में नजर आ रहे हैं. इससे पहले कपिल के टीवी पर 'द कपिल शर्मा शो' और 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' जैसे शो आते थे. एक बार तब कपिल के शो पर सुष्मिता सेन भी पहुंची थीं. कपिल ने अपने शो पर सुष्मिता का हाल चाल पूछा था और 49 साल की सुष्मिता ने जो जवाब दिया था उससे कपिल भी हक्के-बक्के रह गए थे.

'बहुत अच्छी हूं जानेमन...'

कपिल अपने शो पर अपने मेहमानों के साथ जमकर हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं. मजाक-मजाक में कॉमेडियन अपने गेस्ट से उनका हाल चाल भी पूछ लेते हैं. जब सुष्मिता कपिल के शो पर आई थीं तब भी कपिल ने उनसे पूछा था, सुष्मिता कैसी हैं आप ?इस पर एक्ट्रेस ने कहा था, बहुत अच्छी हूं जानेमन, आप कैसे हैं ?

सुष्मिता के जवाब से पिघल गए थे कपिल

सुष्मिता सेन का जवाब सुनते ही दर्शकों और नवजोत सिंह सिद्धू ने जमकर शोर मचाया था और खूब तालियां पीटी थी. कपिल के चेहरे की भी हवाईयां उड़ गई थीं. इसके बाद कपिल ने कहा था, जिसका कभी राशन कार्ड न बना हो, उसको सीधा पासवर्ड मिल जाए तो आदमी ना बौखला जाता है.

49 की उम्र में भी कुंवारी हैं सुष्मिता

सुष्मिता सेन ने साल 1996 की फिल्म 'दस्तक' से डेब्यू किया था और वो अब तक कई फिल्मों-सीरीज में नजर आ चुकी हैं. सुष्मिता के कई अफेयर रहे हैं, हालांकि 49 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस कुंवारी हैं. उन्होंने अब तक शादी नहीं की है. लेकिन, वो बिन ब्याह के दो बेटियों अलीशा और रिनी की मां बनी थीं. दोनों को एक्ट्रेस ने सालों पहले गोद लिया था.

शाहरुख खान की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसे बिहार में गोविंदा की 'दुल्हे राजा' ने कर दिया चारों खाने चित्त

90 के दशक से शाहरुख खान ने हिंदी सिनेमा में अपनी पकड़ बनाई हुई है. सुपरस्टार ने उस दौरान कई ऐसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज कीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर झमाझम पैसों की बारिश की. इतना नहीं कुछ फिल्में तो ऐसी भी थीं, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चरें तक साबित हुईं. साल 1998 में भी शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रिलीज की थी, लेकिन गोविंदा की फिल्म 'दुल्हे राजा' ने उसे बिहार में कमाई के मामले में धूल चटा दी थी. गोविंदा 'दुल्हे राजा' बनकर बिहार में छा गए थे. उनकी फिल्म के आगे किंग खान की पिक्चर टिक नहीं पाई थी.

ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई 'कुछ कुछ होता है' थी. शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर इस लव स्टोरी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. इस फिल्म गानों से लेकर कहानी तक की दर्शकों के दिलों में खास जगह है. राहुल-अंजलि और टीना की कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी.

जब बिहार में दिखा गोविंदा का दबदबा

कम लोगों को ये बात शायद पता हो कि 27 साल पुरानी शाहरुख की फिल्म को गोविंद की 'दुल्हे राजा' ने बिहार में पछाड़ दिया था. इस बात का खुलासा खुद डिस्ट्रीब्यूटर ने किया था. न्यूज18 पर छपी खबर के मुताबिक कोमल नाहटा के साथ बातचीत में करण जौहर ने बिहार में 'कुछ कुछ होता है' के एक डिस्ट्रीब्यूटर से हुई बातचीत को याद किया. उनके सुनाए किस्से ने सभी को दंग कर दिया.

करण जौहर की उम्मीद पर फिरा पानी

करण ने दिल खोलकर डिस्ट्रीब्यूटर का वेलकम किया था. उन्होंने कहा था कि नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं ? कैसी चली है वहां ? इस सवाल का जवाब फिल्ममेकर को लगा था कि बेहतरीन मिलेगा. लेकिन सामने से मिला रिएक्शन उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था. बिहार में फिल्म कुछ कुछ होता है कि परफॉर्मेंस देखने वाले डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि यहां तो फिल्म एवरेज रही.

3 महीने तक बिहार में चली थी फिल्म

डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे जो कहा, उसने करण को हैरान कर दिया. उन्होंने कहा कि यहां तो दूल्हे राजा बहुत बड़ी हिट है. गोविंदा स्टारर दुल्हे राजा को हरमेश मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी. फिल्म में गोविंदा के अलावा रवीना टंडन, कादर खान और जॉनी लीवर ने कलाकार लीड रोल में थे. गोविंदा की पिक्चर ने 3 महीने से ज्यादा समय तक बिहार में अपनी पकड़ बनाए रखी थी.

5 दिन में 132 करोड़ छापकर छा गई 'सैयारा'

श्रद्धा कपूर

ने भी बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ देख डाली फिल्म!

'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया हुआ है. अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस फिल्म के चर्चे बॉलीवुड की गली-गली में हो रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई किए जा रही है. फिल्म को बड़े-बड़े सितारों ने सराहा है. श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ 'सैयारा' देखी. इस रोमांटिक जोड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म देखने के बाद दोनों अपनी सीट से उठकर थिएटर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं.वीडियो में श्रद्धा कैजुअल लुक दिखाई दे रही हैं. उनके साथ राहुल भी हैं. दोनों कैमरों से बचते हुए थिएटर के बाहर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. इससे पहले, श्रद्धा कपूर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर थिएटर से एक वीडियो क्लिप शेयर की थी, जिसमें वह 'सैयारा' देख रही थीं. उन्होंने अहान पांडे के डेब्यू की तारीफ़ करते हुए लिखा, सैयारा से आशिकी हो गई है मुझे.

श्रद्धा ने दिल खोलकर की 'सैयारा' की तारीफ

श्रद्धा ने अहान पांडे, अनीत पड्डा और मोहित सूरी को टैग भी किया. एक अन्य स्टोरी में, उन्होंने लिखा कि यह फिल्म 'पूरी तरह से जादू' है और बहुत लंबे समय के बाद किसी फिल्म को देखकर वह इतनी इंप्रेस हुई हैं. उन्होंने लिखा, प्योर सिनेमाज्योर ड्रामाज्योर जादू. उफ्फज्बहुत समय बाद इतना इमोशन फील किया है. एक्ट्रेस ने 'सैयारा' से अपने पसंदीदा पल का भी खुलासा किया, और उस पल का एक वीडियो क्लिप शेयर किया जब अहान पांडे का किरदार अनीत पड्डा को जंबोट्रॉन पर देखता है और घुटनों के बल गिर जाता है.

श्रद्धा और राहुल के डेटिंग की खबरें

श्रद्धा ने लिखा कि इस पल के लिए 5 बार देखूंगी. श्रद्धा और राहुल की बात करें तो, उनके रिश्ते की अफवाहें 2024 में आनी शुरू हुईं, जब उन्हें बार-बार पब्लिक प्लेस पर साथ देखा जाने लगा. हालांकि श्रद्धा ने डेटिंग की अफवाहों पर पब्लिकली कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपने जीवन में एक जरूरी रिश्ते का हिंट दिया है. उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन को बताया, मुझे अपने पार्टनर के साथ समय बिताना, फिल्म देखना, डिनर पर जाना या घूमना-फिरना बहुत पसंद है. मुझे साथ में समय बिताना या साथ में कुछ न करना भी पसंद है.

नशा तस्करों की पूछताछ पर सुभानपुर से महिला नशा तस्कर काबू

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाई अमल में लाते हुये पकड़े गए नशा तस्करों की निशानदेही पर महिला नशा तस्कर को उसके घर से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस सम्बंधित जानकारी देते हुए एसपी अशोक रतन ने बताया कि पुलिस थाना फतेहपुर के अधीन मुकाम खटियाड़ में नाकाबन्दी के दौरान मोटरसाईकिल स्वार अभय सिंह पुत्र रछपाल सिंह दोनों निवासी गांव मिनता व डा० नरखूँह, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा के कब्जे से 08.14 ग्राम हैरोईन/चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की थी। जिस पर उपरोक्त आरोपियों को गिरफतार करके उनके खिलाफ अभियोग संख्या 70/25 दिनांक 23.07.25 अधीन धारा 21, 25, 29-61-85 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना फतेहपुर में पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में गिरफ्तार आरोपियों से की गई पूछताछ व तथ्यों की जांच से यह पाया गया कि इस अभियोग में अन्य लोग भी शामिल हैं। जिनकी तलाश जिला पुलिस द्वारा भिन्न-2 स्थानों पर की जा रही थी। जिला पुलिस द्वारा पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए दिनांक 24.07.25 को इस अभियोग में शामिल एक अन्य आरोपियों परमजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह गांव हमीरा, डा0 सुभानपुर, जिला कपूरथला, पंजाब को उसके घर गांव हमीरा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी रहेगा।

गांव जामल की निशा ने पहले प्रयास में UGC-NET पास कर रचा कीर्तिमान

दिव्य दिल्ली : विजय आजाद (सिरमौर)

विधानसभा श्री रेणुका जी के तहत विकासखंड सगड़ाह, तहसील नोहराधार की ग्राम पंचायत गवाही के छोटे से गांव जामल की बेटी निशा कुमारी ने पहले ही प्रयास में **UGC-NET** परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने गांव, परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निशा, पूर्व वन विभाग डिप्टी रेंजर श्री दुर्गा राम शर्मा की सुपुत्री हैं। उन्होंने बिना किसी कोचिंग या विशेष संसाधन के, सिर्फ स्व अध्ययन और अनुशासन के बल पर यह सफलता प्राप्त की है। निशा ने यह दिखा दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए हौसला और परिवार का साथ ही काफी है।

न्यूज फ्लैश

नगरोटा सूरियां से प्रधान गुरदेव भारती को प्रदेश उप प्रधान की कमान

दिव्य दिल्ली : प्रेम स्वरूप शर्मा (नगरोटा सूरियां)

पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन खंड नगरोटा सूरियां की मासिक बैठक शुक्रवार को खण्ड प्रधान गुरदेव भारती की अध्यक्षता में विश्राम गृह नगरोटा सूरियां में हुई। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला प्रधान सुरेश ठाकुर को प्रदेश प्रधान व ब्लॉक नगरोटा सूरियां प्रधान गुरदेव भारती को प्रदेश उप प्रधान बनने पर बधाई दी। बैठक में पेंशनरों ने प्रस्ताव पारित कर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश कमान संभालने पर सुरेश ठाकुर को बधाई दी और कहा कि उनका प्रदेश प्रधान बनने से पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और सरकार के साथ एसोसिएशन में समन्वय को और मजबूती मिलेगी। बैठक में गुरदेव भारती ने सरकार से अनुरोध किया कि पेंशनरों के शेष एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए व महंगाई भत्ते व अन्य देनदारियों का भी शीघ्र भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के देय भत्तों व जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों 50 प्रतिशत व 30 प्रतिशत देय भत्तों का भी शीघ्र एकमुश्त भुगतान किया जाए। बैठक में एसोसिएशन के महासचिव सुभाषना भारती, वरिष्ठ उपप्रधान करतार सिंह, कोषाध्यक्ष रामपाल धीमान, बरिष्ठ सलाहकार पीसी विश्वकर्मा, डॉ हरबंस धीमान, शमशेर सिंह जग्गी, शोभा सिंह सैनी, गुरपाल सिंह शास्त्री, प्रवीण मेहरा, किशोरी लाल आदि पेंशनर उपस्थित रहे।

कांता बीएड कॉलेज के चेयरमैन ब समाजसेवी कुलतार सिंह गोल्डी की हृदय गति रुकने से मौत

दिव्य दिल्ली : ऊषा जरियाल (जवाली)

कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन चलवाड़ा के चेयरमैन एवं समाजसेवी कुलतार सिंह गोल्डी का शुक्रवार सुबह हृदयगति रुकने से निधन हो गया जिसमें पूरे जवाली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कुलतार सिंह गोल्डी के अंतिम दर्शन एवं पुष्प श्रद्धांजलि के लिए सैंकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह,भाजपा नेता संजय गुलेरिया, फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया ,मंडल अध्यक्ष डॉ राजिंदर सिंह, कांग्रेसी नेता मनमोहन सिंह कुलतार सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है मृतक कुलतार सिंह गोल्डी का अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा।

108 102 के कर्मचारी परेशान कंपनी नहीं कर रहीं बात

दिव्य दिल्ली : अमरप्रीत सिंह (सोलन)

108 व 102 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी पिछले लम्बे अरसे से कंपनी प्रबंधन पर ष्षोषण के आरोप लगा रहे है। कर्मचारियों के अनुसार उनका शोषण हो रहा है। व उनकी तनख्वाह में भी मई माह में 800 से 1200 रुपये तक काटे गये है। व किसी तरह की सैलरी स्लिप उन्हें नहीं दी जाती । प्रदेश के सभी जिलों के प्रतिनिधि धर्मपुर स्थित 108 के राज्य कार्यालय में अपने खिलाफ दिये गये नोटिस का जवाब देने पहुंचे लेकिन कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों के लिए गेट पर ताला लगा दिया व किसी भी तरह की सार्थक बात करने से इंकार कर दिया । 108 102 कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त ने बताया कि उनकी सैलरी में कट लगाया गया है । जिसके बाद से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की तो कंपनी प्रबंधन द्वारा उन्हें पत्र पर पत्र भेज कर परेशान किया जा रहा है।

उसी का जवाब देने के लिए आज राज्य भर के कर्मचारी यूनियन के प्रधान व अन्य प्रतिनिधि सार्थक बातचीत के लिए आये थे लेकिन कंपनी प्रबंधन ने बात करने से इंकार कर दिया । सुनील दत्त ने बताया कि चार साल बाद कंपनी प्रबंधन ने 500 रुपये तनख्वाह बढ़ाई है जिसके लिए वह मिठाई देने भी आये थे । लेकिन कंपनी के इस तरह के रवैये से वह नाराज है व आगे से उन्हें परेशान न करने की मांग कंपनी से की है

शाहपुर कंडी बैराज बांध विस्थापित परिवारों ने चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर विशाल रोष प्रदर्शन व धरना दिया

विभाग के कर्मचारियों के लिए बैठने के लिए भी जगह कम है एक कमरे में ही बैठकर सारा काम करना पड़ता है

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

शाहपुर कंडी में डैमेज प्रशासन के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर बैराज बांध की बनी हुई झील से विस्थापित हुए परिवारों ने अपने रोजगार व अन्य मुआवजे की मांग को लेकर 114वें दिन भी अपनी भूख हड़ताल व रोष प्रदर्शन बैराज बांध औसती संघर्ष कमेटी शाहपुर कंडी के बैनर तले जारी रखा । आज 114वें दिन पर जसवीर सिंह सिंबला, सुरिंद्र सिंह सिंबला, अवधेश शर्मा राम शाहपुर कंडी, आशीष महाजन शाहपुर कंडी व अभिषेक अदियाल ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। विस्थापित परिवारों व कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि , बैराज बांध प्रशासन व पंजाब सरकार ने बैराज बांध की बनी हुई झील के लिए उनके कई गांवों से उनकी भूमि व आवासों को अधिग्रहित किया है, परंतु बनती आर एंड आर पालिसी अनुसार, न तो रोजगार तथा न ही पुनर्वास मुआवजा दे रही है, जिस कारण प्रभावित हुए परिवार पिछले चार माह से लगातार रोष प्रदर्शन व भूख हड़ताल कर रहे है। रोष प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि पुरानी आर एंड आर पॉलिसी को बहाल किया जाए , उनका बनता रोजगार दिया जाए व पुनर्वास मुआवजा दिया जाए । इसके साथ ही विस्थापित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी उचित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह तीस जुलाई को फिर से चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर विशाल रोष प्रदर्शन व धरना देगें।

इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी , कर्मचारी नेता जसवंत संधू, रविंद्र बाबा, युवराज सिंह, रजन बलोतरा, रोहित कुमार, सुरजीत सिंह, जसविंदर सिंह,अवेधश शर्मा ,विनोद शर्मा, धर्मपाल, रमेश कुमार, आदर्श वाला, विनोद कुमारी, बीतू देवी, यशोदरा देवी, हरनाम सिंह , अंशू शर्मा व अन्य उपस्थित थे। डैमेज प्रशासन के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र कुमार ने प्रभावित परिवारों से बैठक करके बताया कि, उनके कार्यालय की ओर से पूरी सूचना , जल स्त्रोत विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दी गई तथा जैसे जल स्त्रोत विभाग के उच्चाधिकारी आदेश जारी करेगा,वह वैसा ही करेगें।

जिला बाल संरक्षण विभाग ने बाल भिक्षावृत्ति रोकने हेतु विभिन्न स्थानों पर छापे मारे

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

श्री भगवंत सिंह मान, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए जीवन ज्योति अभियान के अंतर्गत, आज पठानकोट के उपायुक्त श्री आदित्य उप्पल के निर्देशन में, पठानकोट शहर में बाल संरक्षण विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, श्रीमती रेणु, पठानकोट की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए और भीख मांगते बच्चों को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान, कुछ स्थानों पर बच्चों के अभिभावकों से बातचीत और जांच-पड़ताल के बाद, निर्देश जारी कर उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि शनिदेव मंदिर के पास भीख मांग रहे एक बच्चे को पकड़ा गया।इस अवसर पर जानकारी देते हुए पठानकोट की जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रेणु ने बताया कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री के निदेर्शों के तहत शहर में विशेष रूप से सड़कों पर और विभिन्न धार्मिक स्थलों के बाहर भीख मांगने वाले बच्चों पर छापेमारी की गई।

इस दौरान भीख मांगती एक लड़की को पकड़ा गया और कुछ मामलों में छापेमारी में पकड़े गए बच्चों के अभिभावकों से विशेष बातचीत के बाद निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि आज की कार्रवाई सरकार के अभियान जीवन ज्योति के तहत की गई है और ये छापेमारी 31 जुलाई 2025 तक पठानकोट जिले में जारी रहेगी। इस दौरान पठानकोट जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जाएगी। इस कार्य में संलिप्त पाए गए बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ नियमों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। अगर पकड़े गए बच्चों के अभिभावक बच्चे से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ऐसे में बच्चों को निर्धारित आश्रय गृहों में भेज दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर राम लुभाया जिला लोक संपर्क अधिकारी पठानकोट, लवमीत कौर, श्वेता शर्मा, इंद्रजीत सिंह, रूबी शर्मा, डॉ. गौरव शर्मा, नीलम कुमारी शिक्षा विभाग, अमनदीप कौर एसडीपी नगर निगम, सीमा श्रम विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

हमीरपुर के कृष्णानगर में घर में सेंधमारी

दिव्य दिल्ली : समित कुमार (हमीरपुर)

हमीरपुर शहर के कृष्णा नगर में एक घर में हुई सेंधमारी की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। चोरी के इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। एसपी भगत सिंह ने बताया कि यह मामला वार्ड नंबर 1, कृष्णानगर निवासी हिना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि रात को कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा, सुरक्षा कैमरे तोड़ डाले और कंप्यूटर व नकदी चुराकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर हमीरपुर की टीम ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की। जांच में सामने आए आरोपी सूरज शर्मा निवासी मकान नंबर 268, कृष्णानगर और ललित ठाकुर निवासी गांव कोलहड़ी, झनियारा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इनके पास से चोरी की गई कंप्यूटर यूनिट बरामद कर ली गई। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ने बताया कि ड्रग डिडक्शन किट के माध्यम से जिला हमीरपुर पुलिस ने लगभग ढाई सौ के करीब टेस्ट किया जा चुके हैं। जिसमें 50: पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। एसपी हमीरपुर ने बताया कि कुछ हद तक नशे पर लगाम लगी है तथा जिन लोगों के टेस्ट पॉजीटिव पाए गए हैं वह कहीं ना कहीं चोरी की घटनाओं में भी शामिल रहे हैं

घायल घोड़ी के बच्चे को ढूंढकर ऑपरेशन कर माँ के साथ मिलाया

दिव्य दिल्ली : करूनीत रंधावा (पठानकोट)

जिला पठानकोट के प्रमुख समाजसेवी व उभरते युवा नेता सृज्ल गुप्ता ने युवाओं, उद्यमियों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को जागरूक करते हुए कहा, " जो तलाशता है उसे खामी दिखेगी और जो तराशता है उसे खूब दिखेगी।" उनका यह शब्द न केवल प्रबंधन और नेतृत्व के मूल्यों को दशार्ता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने कहा कि जीवन में तरक्की उसी को मिलती है जो हर व्यक्ति, परिस्थिति और अनुभव में अच्छाई देखने का नजरिया रखता है। सृज्ल गुप्ता ने कहा कि दुनिया में हर चीज में दो पहलू होते हैं-एक अच्छा और एक बुरा। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह किस दृष्टिकोण से देखता है। यदि हम किसी में कमी ढूंढने पर ध्यान देंगे तो वह चीज भी नकारात्मक लगने लगेगी, जिसमे सच्चाई हो सकती है। परंतु यदि हम उसे सुधारने, तलाशने और उसकी अच्छाइयों को देखने का प्रयास करें, तो वही चीज प्रेरणा बन सकती है

इनर व्हील क्लब की महिला सदस्यों द्वारा आज पौधारोपण किया गया

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर वन विभाग के साथ मिलकर इनर व्हील क्लब नूरपुर ने गही लगोड़ पंचायत में आज एक पेड़ मां के नाम के पौधा रोपण प्रोजेक्ट के कार्यक्रम का आयोजन किया' यह जानकारी एक प्रेस विज्ञाप्ति में इनर व्हील क्लब की प्रधान नीति महाजन पत्नी गौरव महाजन नगर पार्षद नूरपुर जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश ने देते हुए बताया कि नूरपुर वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा द्वारा क्लब को इस अवसर पर 5100/रुपए ईनाम के रूप में दिए गए हैं' यह क्लब के लिए पहली वार प्रशंसनीय कदम है' आज तक किसी ने भी क्लब को सम्मानित नहीं किया ' नीति महाजन ने इस अवसर पर नूरपुर वन उपमंडल अधिकारी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद किया और आश्वासन दिया की वन विभाग समय-समय पर पौधारोपण के मामले में इनर व्हील क्लब के सदस्यों का सहयोग लेता रहेगा' क्लब द्वारा भी वन विभाग के इस सहयोग से वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बेस्ट ऑफ कॉरपोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया' कार्यक्रम में नूरपुर वन मंडल अधिकारी अमित शर्मा व उनके स्टाफ के कर्मचारियों ने इनरवियर क्लब महिला बिंग के साथ इस पौधारोपण में पूरा सहयोग दिया तथा पौधारोपण के बारे में पूरी जानकारी दी '"एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत गांव गहीं लगोड़ पंचायत भूमि में पौधारोपण आज इनर व्हील क्लब के द्वारा महिला संपन्न हुआ ' शमार्ने इस अवसर पर क्लब की सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं देश में अगर जागरूक हो जाए तो देश में पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा।

' उपमंडल अधिकारी अमित शर्मा, सहायक वन संरक्षक निशांत पराशर एवं वन मंडल कर्मचारी गण के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के लगभग 150 जंगली एवं औषधीय पौधे लगाए कपौधारोपण के लिए पौधे वन विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाए गए कइस अवसर पर शर्मा ने इन पौधों की महत्ता एवं संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

इनरव्हील क्लब ऑफ सोलन मिडटाउन ने करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया

दिव्य दिल्ली : अमरप्रीत सिंह (सोलन)

इनरव्हील क्लब ऑफ सोलन मिडटाउन ने शेड्स लॉ कॉलेज के अनुरोध पर 'उड़ान' के तहत एक प्रेरणादायक करियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में क्लब की एडिटर पवन पुरी, रिटायर्ड सीईओ ने अपने न्यायिक विभाग के अनुभवों को साझा करते हुए छात्रों को कानून के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बारे में बताया, जैसे कि खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर एक अच्छा वकील बनकर सिविल और क्रिमिनल साइड में काम करना, सरकारी वकील ,एचजेएस पास कर के जज बनना और निजी क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाना। इस सत्र का उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार भविष्य तय करने में मदद करना और उन्हें प्रेरित करना था। क्लब की प्रधान अंजू पबियाल ने भी अपने अनुभवों से छात्रों को उत्साहित किया।कार्यक्रम में क्लब की सदस्य ज्योति आनंद और सोनिका सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

अंत में, शेड्स लॉ कॉलेज की चेयरपर्सन, सुनीता ठाकुर ने क्लब के सदस्यों का धन्यवाद किया और विशेष रूप से सम्मानित किया।

श्री रेणुका जी बांध विस्थापितों की समस्याएं बरकरार

दिव्य दिल्ली : विजय आजाद (सिरमौर)

श्री रेणुका जी बांध विस्थापित संघर्ष समिति की कोर कमेटी ने हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय, दादाहू में एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर विस्थापित परिवारों की ज्वलंत समस्याओं और मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। समिति ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक बांध निर्माण कार्य को शुरू नहीं होने दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपते हुए समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि पिछले 17 वर्षों से विस्थापितों ने लगातार अपनी मांगों को सरकार और प्रशासन के समक्ष उठाया है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, समाधान नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए हमने अपनी पुश्तैनी जमीन सरकार को दीं, लेकिन बदले में हमें जो पुनर्वास की जमीन मिली है, उसका 90% हिस्सा नदी में समाया हुआ है, जहां रहना तो दूर, टिक पाना भी मुश्किल है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397